मेट्रो Rays

आगे रखने का वादा

सांध्य दैनिक

रांची, शुक्रवार, 25 सितंबर 2026

संवत 2083, भाद्रपद शुक्ल 14 मूल्य-2 रुपये

वर्ष-10, अंक 21 , पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

4 ▶▶ क्या कल्याणकारी से पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा भारत?

'क्या तकलीफ है'? कोमल रानी संग डेटिंग रूमर्स पर चीची ने तोड़ी चुप्पी, चर्चा करने वालों पर फूटा गुस्सा 6

रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट राजधानी में हवा के साथ बरस रहे हैं बादल

▶ रांची में तेज बारिश-हवा का असर, 4 विमान डायवर्ट, दिल्ली फ्लाइट की बदली टाइमिंग ▶ डैमो में भरा पानी,लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त- व्यस्त

संवाददाता

रांचीः बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया उत्तरी आंध्रप्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट को पार कर गया है। इससे असर झारखंड में दिख रहा है। मौसम के प्रभाव से झारखंड के कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी है। राजधानी रांची में आज सुबह से ही तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 25 सितंबर को झारखंड में भारी बारिश के साथ गरज, वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है।

सात जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्टः बंगाल की खाड़ी में बने गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण गुरुवार को झारखंड के कई जिलों में बादल छाये रहे और रुक-रुक कर बारिश हुई। रांची में नौ मिमी बारिश दर्ज की गयी। राज्य में सबसे अधिक 43.5 मिमी बारिश बहरागोड़ा में हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 25 सितंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, रांची समेत अन्य जिलों में मौसम धीरे-धीरे साफ होने की संभावना है, हालांकि बादल छाये रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश व तेज हवा चल सकती है।

अब भी सामान्य से 05 प्रतिशत कम बारिशः झारखंड में अभी भी सामान्य से पांच प्रतिशत कम बारिश हुई है। झारखंड में एक जून से 24 सितंबर तक सामान्य रूप से 984.7 मिमी बारिश होती है, लेकिन अब तक 935.7 मिमी ही बारिश हुई है। वहीं, रांची में इस अवधि में सामान्य बारिश 1003.2 मिमी है, जबकि अब तक यहां 1127 मिमी बारिश हो चुकी है। यानि 12 प्रतिशत अधिक बारिश हो गयी है। वहीं, पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से 43 प्रतिशत, सरायकेला में 17, लोहरदगा में तीन, लातेहार में 13 व पूर्वी सिंहभूम में सात प्रतिशत अधिक बारिश हो गयी है। पाकुड़, चतरा, देवघर, गुमला, साहिबगंज, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा में अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है।

धनबाद में सबसे अधिक 128.6 मिमी वर्षा दर्ज, कमजोर हुआ तूफानः बंगाल की खाड़ी से बने गहरे दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र के अनुसार, पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश धनबाद के बाघमारा में दर्ज की गई। राजधानी रांची में भी बारिश का असर रहा।रांची एयरो में 52.6 मिमी, जबकि बीएयू कांके में 102.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा नंदीह में 123.6, पुटकी सीडब्ल्यूसी में 118.4, पालगंज में 105, कुकुर में 98.6 और निमडीह में 97.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के ऊपर सक्रिय है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए शाम तक धीरे-धीरे कमजोर डिप्रेशन में बदल चुका है। इसके बाद अगले 24 घंटे में इसके और कमजोर होने की संभावना है।

25 और 26 सितंबर को भी बारिश के आसारः शुक्रवार को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं शनिवार को भी राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी।वहीं अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 27 और 28 सितंबर को भी राज्य में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है।

ज्ञानेश कुमार पर लगे गंभीर आरोप, महाभियोग की तैयारी

नई दिल्लीः देश में निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग के कंधों पर है, उसकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर संदेह जताए जा रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के रोल पर सवाल उठाते हुए इसे देशद्रोह ठहरा रही है। वहीं, हालिया जेन जी आंदोलन से सुर्खियों में आई कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सीईसी को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केस चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां संसद के शीतकालीन सत्र में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी में हैं। वहीं, केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) खुलकर सीईसी के बचाव में उतर आई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने तो ज्ञानेश कुमार को पद्मश्री देने की मांग कर दी है।

ज्ञानेश कुमार पर आरोप क्या? : एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर, चुनाव आयोग के अंदर मतभेद और वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर विवाद का दावा किया गया है। रिपोर्ट में उएउ पर मुख्य रूप से दो गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर आरोप है। इस प्रक्रिया में मतदाता सूची को दोबारा जांचा और अपडेट किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए।

दूसरा आरोप यह है कि दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता डेटा के केंद्रीकरण, नाम हटाने और कुछ मतदाताओं के नाम जोड़ने से जुड़े मामलों पर आपत्ति जताई थी। इसके लिए पिछले 10 महीनों में आयोग की प्रक्रियाओं और फैसलों को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थीं, जिन्हें कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया। मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरी', 'संस्था चोरी' और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए इसे 'देशद्रोह' करार दिया है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने ये आरोप सिरे से नकार दिए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि फैसले सभी तीन आयुक्तों की सहमति से ही लिए गए। विपक्ष की मांग- हो स्वतं जांचः सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोप लेकर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 24 सितंबर को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दी। उन्होंने एसआईआर और वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों में कथित आपराधिक आचरण की जांच और एफआईआर की मांग की है। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्युनिटी मिली हुई है और सीईसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता।

एशियन गेम्स : सोने पर निशाना, शूटिंग में भारत ने जीता स्वर्ण पदक, सुरुची और कमलजीत का कमाल

आइची-नागोया-जापानः सुरुचि सिंह और कमलजीत ने शुक्रवार को यहां एशियाई खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रुद्राक्ष, नीरज और ऐश्वर्य की टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। आज यहां सुरूचि सिंह और कमलजीत ने सटीकता और संयम का बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए 484।6 अंकों के नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता। भारतीय जोड़ी, जिसने 587-29& के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया था ने फाइनल में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। वे मुकाबले के ज्यादातर समय आगे रहे और अंत में दक्षिण कोरिया की चुनौती को पीछे छोड़ते हुए 6।6 पॉइंट्स के अंतर से जीत हासिल की। कोरियाई जोड़ी 478।0 अंक के साथ रजत पर रही, जबकि ईरान ने 415।8 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक जीता।

इस जीत के साथ आइची-नागोया खेलों में स्वर्ण पदक में स्वर्ण पदक का भारत का इंतजार खत्म हुआ और उस अभियान में एक और उपलब्धि जुड़ गई जिसमें शूटर्स पहले ही कई मेडल जीत चुके थे। सुरुचि और कमलजीत, दोनों ही इंडिविजुअल फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन उन्होंने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया और मिक्स्ड टीम का खिताब दांव पर होने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनके जीतने वाले स्कोर ने 481।3 के पिछले एशियाई रिकॉर्ड को भी 3।3 पॉइंट्स से पीछे छोड़ दिया, जो खेलों के मंच पर उनके शानदार प्रदर्शन को दशार्ता है। अब भारत के स्वर्ण पदक की संख्या दो हो गई है; इससे पहले महिला क्रिकेट टीम ने एक और खिताब जीता था। भारतीय जोड़ी क्वालिफिकेशन में दबदबा बनाने के बाद फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने 196, 195 और 196 की सीरीज के साथ चार टीमों के मुकाबले में टॉप स्थान हासिल किया था। एक अन्य मुकाबले में पुरुषों के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल की तिकड़ी ने रजत पद जीतकर एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या में एक और इजाफा किया। भारतीय तिकड़ी ने कुल 1762-94& का स्कोर किया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही।

चीन ने 1766-95& के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया ने 1751-87& के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन राउंड में ऐश्वर्य ने भारत की चुनौती की अगुवाई की, उन्होंने 589-34& का स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि नीरज 588-34& के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। दोनों ने व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाई, जिससे भारत को इस इवेंट में अपने पदकों की संख्या बढ़ाने का एक और मौका मिला। रुद्राक्ष 585-26& के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहे और व्यक्तिगत फाइनल में जगह नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने आइची-नागोया में अपने पदकों के संग्रह में एक और पदक जोड़ा। इससे पहले उन्होंने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य और टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। ऐश्वर्य और नीरज के व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचने के साथ ही 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भारत की चुनौती जारी है और ये दोनों खिलाड़ी एक और पदक के लिए मुकाबला करेंगे।

सिक्किम में लैंडस्लाइड, 20 से ज्यादा घर बहे

नईदिल्ली/पटना/लखनऊ/भोपाल/जयपुरः सिक्किम के ग्यालशिंग जिले के रिंबी गांव में लगातार बारिश के कारण गुरुवार रात लैंडस्लाइड हुई। इसमें 20 से ज्यादा घर और सरकारी क्वार्टर बह गए। हालांकि, अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है।

बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात अब कमजोर पड़ गया है। इसके कारण ओडिशा में भारी बारिश के साथ अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में निचले और लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले करीब 10 हजार लोगों को 200 राहत केंद्रों में भेजा गया है। चक्रवात से 9 राज्य प्रभावित हैं। अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। जबलपुर समेत 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में आज 19 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है। हरियाणा में भी यमुनानगर, करनाल और पानीपत समेत 6 जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं, यूपी में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। आज सुबह से लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर समेत 20 शहरों में बारिश का दौर जारी है। लखनऊ में गुरुवार शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है।

8-10 लोगों ने मिलकर कर दी दारोगा के बेटे की हत्या

जेएमएम छात्र मोर्चा से जुड़ा था युवक

गिरिडीहः जिले के प्रसिद्ध मैगी पॉइंट के पास एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार की रात लगभग 11 बजे की है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना इलाके के राजेंद्र नगर (बभनटोली) निवासी ऋतिक यादव ऊर्फ बड्डी यादव (24 साल) के रूप में हुई है। घटना के बाद मुफस्सिल पुलिस सभी आरोपियों की खोज में जुटी है। मृतक के पिता झारखंड पुलिस के एसआई पद पर पदस्थापित हैं।

घटना को लेकर सदर अस्पताल में मृतक के साथी शुभम दास ने बताया कि रात लगभग 10.30 में वह, उसका दोस्त राजा गुप्ता और ऋतिक यादव कार पर सवार होकर गिरिडीह-डुमरी पथ पर अवस्थित बंदरकुप्पी गए थे। यहां मैगी पॉइंट है, जहां रातभर मैगी, कॉफी और चाय मिलता है।

तभी पीरटांड थाना इलाके के नावाडीह निवासी सतीश यादव अपने 8-10 साथियों के साथ वहां पहुंचा और अचानक उनपर हमला कर दिया। पहले उन्होंने मुक्के से वार किया। मुक्के की पिटाई में कुछ नहीं हुआ तो फिर बांस की फराठी (बांस का टुकड़ा) से पिटाई शुरू कर दी। इतना पीटा कि ऋतिक की जान ले ली। उन्होंने बताया कि अचानक हमला किया गया, फिर ऋतिक को पीटते हुए उसकी जान ले ली।

पिता हैं एएसआईः इधर घटना की सूचना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह भी पहुंचे। रॉकी ने बताया कि ऋतिक की घटना से लोग सकते में हैं। उन्होंने कहा कि ऋतिक के पिता पुलिस महकमा में सहायक अवर निरीक्षक हैं और अभी बोकारो के चतरोचट्टी थाना में पदस्थापित हैं। वहीं मृतक ऋतिक यादव का सम्बन्ध छात्र संघ से था। उन्होंने बताया कि घटना काफी दुःखद है। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने भी ऋतिक को मृत घोषित कर दिया है। वहीं इस घटना में दो अन्य युवक को भी चोट लगी है। मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारी से बात हुई है। पुलिस की टीम भी छापेमारी में जुटी है।

पुलिस ने की छापेमारीः इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने पहले घायलों को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद आरोपियों की खोज में छापेमारी शुरू की। बताया जाता है कि मामले को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सूचना पर नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी सदर अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ऋतिक यादव की हत्या की गई है। आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है।

म्यांमार सीमा पार से आए हथियारबंद आतंकियों ने मणिपुर में की 4 लोगों की हत्या, 24 घंटे का बंद घोषित

इंफाल : मणिपुर के सीमावर्ती कामजोंग जिले में गुरुवार दोपहर एक बार फिर खून-खराबा देखने को मिला। इंडो-म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर 95 के समीप बसे पिलोंग गांव में हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर पिता-पुत्र समेत चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह इलाका चासाड पुलिस स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि हमलावर म्यांमार सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में घुसे थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ने भागकर बचाई जान, गांव पहुंची पुलिस और असम राइफल्सः गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुए इस अचानक हमले से गांव में अफरा-तफरी मच गई।

हाफिज सईद पर मुकदमा कब चलाएंगे? यूएन में सवाल सुनकर पाक पीएम शहबाज शरीफ ने साधी चुप्पी

न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हाफिज सईद के मुद्दे पर सीधे सवालों का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश करते समय एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेगा। शहबाज शरीफ ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। बाद में जब वह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से बाहर निकले तो पत्रकार ने उनसे फिर सवाल किया कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद पर मुकदमा कब चलाया जाएगा। इस सवाल पर भी शहबाज शरीफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए।

शहबाज शरीफ से पूछे गए दोनों सवाल पाकिस्तान में आतंकवाद और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े थे। प्रवेश के दौरान पत्रकार ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेंगे? लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से निकलते समय उनसे पूछा गया, लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद पर मुकदमा कब चलाएंगे? इस सवाल पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के आतंकवाद संबंधी रिकॉर्ड और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और प्रमुख रहा है। भारत ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में भी उसका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है।

न्यूज IN ब्रीफ

नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर 32 लाख के लूटकांड का उद्भेदन

चतरा : बीते 7 सितंबर को चतरा से बिहार के गयाजी जा रही स्टार फीस नामक यात्री बस से वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर दो यात्रियों से 31 हजार 90 हजार रु की लूटकांड का चतरा पुलिस ने उद्भेदन करते हुए बिहार और झारखंड के पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 70 हजार रु भी बरामद किए गए हैं। जिला मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी(मु) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बीते 7 सितंबर को चतरा जिले के पत्थलगड्डा थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव के ललन कुमार (28 वर्ष) ने वशिष्ठ नगर थाना में आवेदन देकर बताया था कि अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा अपने आप को नारकोटिक्स विभाग का स्टॉफ बताकर कर धोखाधड़ी कर 31 लाख 90 हजार रूपया लूट लिया था। इस संदर्भ में वशिष्टनगर थाना कांड संख्या 131/2026 दिनांक-07.08. 2026, धारा-319 (2)/310 (2) बीएनएस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि कांड की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि तकनिकी साक्ष्यों एवं लोकल इनपुट के आधार पर थाना क्षेत्र के कटैया जंगल और कंगुरूवा जंगल से बिहार के गयाजी जिले के धनगाईं थाना क्षेत्र के महंगाई गांव के रंगु कुमार पिता दिनेश यादव,धनगाई थाना क्षेत्र के सोखिया गांव निवासी अभिषेक कुमार पिता केशर यादव,बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पिपराही गांव के प्रिंस कुमार यादव पिता सहदेव यादव, हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के केदली कला गांव के अविनाश कुमार पिता सुनिल कुमार एवं चौपारण थाना क्षेत्र के चौपारण गांव निवासी बजरंगी कुमार उर्फ रंगा पिता स्व० ब्यास यादव को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने आगे बताया कि लूटकांड में प्रयुक्त काले रंग का थार और 70 हजार रु नगद बरामद किया गया है। छापामारी दल में पुअनि सह वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह, पुअनि सह प्रतापपुर थाना प्रभारी आलोक रंजन,पुअनि सह इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, वशिष्ठ नगर थाना के पुअनि शिवा यादव, तकनीकी शाखा चतरा के आरक्षी विरेन्द्र यादव एवं थाना सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

जिले के स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की बैठक

चतरा : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने, निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने तथा जिला निर्यात कार्य योजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में चतरा जिले में उत्पादित विभिन्न कृषि एवं स्थानीय उत्पादों की निर्यात क्षमता पर चर्चा की गई। विशेष रूप से टमाटर की प्रचुर उत्पादकता को देखते हुए इसके प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कृषि एवं खाद्य उत्पाद, स्थानीय खाद्य उत्पाद, मत्स्य एवं मीट आधारित उत्पादों सहित अन्य संभावित उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।उपायुक्त ने संभावित निर्यात उत्पादों के चयन के दौरान उत्पादन क्षमता, बाजार की मांग, उत्पाद की गुणवत्ता, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की सुविधा तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात की व्यवहार्यता को प्रमुख आधार बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप प्रमाणन, आवश्यक आधारभूत संरचना, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बाजार संपर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।बैठक में जिले से संभावित उत्पादों के निर्यात में आने वाली चुनौतियों, गुणवत्ता एवं प्रमाणन संबंधी आवश्यकताओं तथा निर्यात के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित विभागों को स्थानीय उत्पादों की पहचान कर उनकी उत्पादन क्षमता एवं बाजार की संभावनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी संकलित करने तथा जिला निर्यात कार्य योजना को प्रभावी रूप से तैयार करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, हजारीबाग (कैंप कार्यालय, चतरा) शंभू शरण बैठा, अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा

मरकच्चो (कोडरमा): मरकच्चो पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में मंडलकारा कोडरमा भेज दिया। पुलिस के अनुसार मरकच्चो थाना कांड संख्या 69/2026, दिनांक 23 सितंबर 2026, धारा 64/79 बीएनएस के प्राथमिकी अभियुक्त शशि कुमार पंडित उर्फ शशि कुमार (20), पिता मनोज प्रजापति, ग्राम सिंघरावां, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग, वर्तमान पता ग्राम जगदीशपुर, थाना मरकच्चो, को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि अभियुक्त ने मरकच्चो थाना क्षेत्र की एक युवती के घर में जबरन प्रवेश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी बमबम कुमार ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी है।

टंडवा में पीएनएम-ओएसएल-हिंडालको का कोयला परिवहन बना चुनौती

कोयला ढुलाई से सड़कें बेहाल, ग्रामीणों की सुरक्षा पर रहे उठ हैं सवाल

मेट्रो रेज

चतरा : कभी शांत और सामान्य आवागमन वाला टंडवा कोयलांचल क्षेत्र आज भारी कोयला वाहनों की आवाजाही, जाम, धूल, सड़क क्षति और हादसों की बढ़ती चिंता से जूझ रहा है। आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र से कोयला ढुलाई में लगी पीएनएम, ओएसएल, हिंडालको समेत विभिन्न परिवहन कंपनियों की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकारी स्तर पर भी टंडवा में बढ़ते भारी वाहनों के दबाव से सड़क पर तनाव, धूल और जाम की समस्या दर्ज की जा चुकी है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कम लागत या अधिक मुनाफा कमाने की लालच में परिवहन व्यवस्था का बोझ आम सड़कों पर डाल दिया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। शिवपुर साइडिंग तक जाने वाले मार्गों की स्थिति और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि सितंबर 2026 में सीसीएल ने शिवपुर रेलवे साइडिंग के तहत कोयला परिवहन सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है, जो सड़क की स्थिति पर उठ रहे सवालों को और महत्वपूर्ण बनाता है।
अनफिट वाहनों और रफ्तार पर कौन लगाएगा लगाम?
ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला ढुलाई में लगे कुछ वाहनों की फिटनेस, गति और संचालन व्यवस्था की नियमित जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो रही है। आरोप यह भी है कि निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए भारी वाहन आबादी वाले रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं।
मई 2026 में टंडवा क्षेत्र में तेज रफ्तार कोल हाइवा की चपेट में आने से दो युवकों की मौत की घटना सामने आई थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर भारी वाहनों की रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।
सवाल सीधा है–अगर नियम मौजूद हैं तो उनका पालन कौन करवा रहा है और उल्लंघन होने पर कार्रवाई कौन कर रहा है?
टोकन मनी और अतिरिक्त ट्रिप का आरोप–किसके इशारे पर?
ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ परिवहन व्यवस्था में चालकों को अधिक ट्रिप लगाने के लिए कथित रूप

से अतिरिक्त प्रोत्साहन अथवा टोकन मनी दिए जाने की व्यवस्था है। यहां तक कि शराब सेवन के लिए पैसे दिए जाने जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। यदि ऐसा कोई भुगतान वास्तव में किया जा रहा है, तो इसकी जांच परिवहन कंपनियों, सीसीएल और जिला प्रशासन को रिकॉर्ड, भुगतान विवरण, ट्रिप शीट, जीपीएस और वाहन लॉग के आधार पर करनी चाहिए।
मोहन की भूमिका पर भी उठ रहे सवालः पीएनएम कंपनी से जुड़े मोहन की भूमिका को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रभाव और ऊंची पहुंच के कारण उनकी भूमिका को लेकर शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।
इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, दबाव बनाने या परिवहन व्यवस्था में हस्तक्षेप के ठोस प्रमाण हैं, तो संबंधित दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने के बजाय जांच के बाद जिम्मेदारी तय करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
मुआवजे का पैसा कहां गया?
सबसे गंभीर सवाल उन परिवारों का है जिन्होंने कोयला परिवहन से जुड़े हादसों में अपने परिजनों को खोया है। ग्रामीणों का दावा है कि कई मृतकों के परिजनों को अब तक कथित रूप से पूरी मुआवजा राशि नहीं मिली है।
आरोप यह भी है कि टंडवा-केरेडारी-पिपरवार क्षेत्र में मुआवजा राशि के नाम पर कंपनियों से रकम एकत्र की जाती थी। यदि ऐसा हुआ है तो बड़ा सवाल है–किसने राशि जमा की, किस खाते में गई, कितनी राशि किस परिवार को दी गई और कितनी राशि अब भी बकाया है?
इस पूरे मामले में कंपनीवार और मृतकवार भुगतान का सार्वजनिक विवरण सामने आना चाहिए।
15 रुपये प्रति टन का रहस्य क्या है?
कोयला ढुलाई व्यवस्था में 15 रुपये प्रति टन के कथित लेन-देन को लेकर भी चर्चाएं हैं। यदि यह आरोप निराधार है तो संबंधित कंपनियों को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और यदि वास्तव में किसी प्रकार की राशि ली या दी जा रही है, तो उसका उद्देश्य, प्राप्तकर्ता, भुगतान प्रणाली और वैधानिक आधार सार्वजनिक होना चाहिए।
आखिर 15 रुपये प्रति टन की कहानी क्या है?
यही वह सवाल है जिसका जवाब सामने आने पर परिवहन व्यवस्था में चल रहे कथित आर्थिक खेल की तस्वीर साफ हो सकती है।
कुर्सी बदलती रही, व्यवस्था क्यों नहीं बदली?
कोयला ढुलाई में मैनुअल, गेट, ट्रिप, चालान और वाहन संचालन से जुड़े स्तरों पर काम करने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में होनी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ पदों पर बैठे लोगों की आमदनी और प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
अगर आरोप गलत हैं तो जांच कर उन्हें खारिज किया जाए। अगर सही हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।
अब जरूरत किसकी पहुंच कितनी की नहीं, जवाबदेही की है
टंडवा में कोयला उत्पादन और परिवहन क्षेत्र की आर्थिक भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास की कीमत ग्रामीणों की जान, सड़क और सुरक्षा नहीं हो सकती। केंद्र सरकार के समक्ष दिए गए जवाब में भी टंडवा में बढ़ते भारी वाहनों के कारण सड़क पर दबाव, धूल और जाम की समस्या स्वीकार की गई है तथा रेल कनेक्टिविटी और फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी के जरिए सड़क परिवहन का दबाव कम करने की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। अब जरूरत है कि सीसीएल, जिला प्रशासन, जिला परिवहन विभाग और संबंधित परिवहन कंपनियां संयुक्त रूप से जवाब दें–
- कितने वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ चल रहे हैं?
- कितने वाहनों पर पिछले एक वर्ष में कार्रवाई हुई?
- ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग की कितनी जांच हुई?
- प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन कितने ट्रिप की अनुमति है?
- कथित अतिरिक्त ट्रिप प्रोत्साहन की जांच हुई या नहीं?
- हादसों में मृतकों के परिजनों को कितनी मुआवजा राशि दी गई?
- कितनी राशि अब भी बकाया है?
- कथित 15 रुपये प्रति टन राशि का कोई रिकॉर्ड है या नहीं?
- शिवपुर साइडिंग तक सड़क की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है?
टंडवा कोयला देता है, रोजगार देता है और देश की ऊर्जा जरूरतों में योगदान देता है। लेकिन बदले में उसे जाम, धूल, टूटी सड़क और हादसों का स्थायी बोझ नहीं मिलना चाहिए। अब सवाल सिर्फ कोयला ढुलाई का नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा, पारदर्शिता

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पत्र का असर, सड़क निर्माण की जांच शुरू

मेट्रो संवाददाता

सतगावां (कोडरमा): दर्शनपुल से बासोडीह होते हुए गावां को जोड़ने वाली नवनिर्मित सड़क के निर्माण में कथित अनियमितता और गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार को उच्चस्तरीय जांच टीम ने सड़क का स्थल निरीक्षण किया। पथ प्रमंडल द्वारा करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया है। निर्माण के महज एक महीने बाद पहली बारिश और सामान्य आवागमन के दौरान सड़क के कई हिस्सों के खराब होने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। हाल ही में पत्रकारों ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी मामले से अवगत कराया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।इसी बीच कुछ दिन पूर्व इसी जर्जर सड़क पर हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर घंटों सड़क जाम कर विरोध जताया था। मौके पर पहुंचे बीडीओ मनोज कुमार रवि और थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया था। इसके बाद सड़क निर्माण की जांच की मांग और तेज हो गई थी।मामले को लेकर हजारीबाग पथ अंचल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के नेतृत्व में उच्चस्तरीय जांच टीम सड़क पर पहुंची। टीम में पथ प्रमंडल धनबाद के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार, हजारीबाग के कार्यपालक अभियंता सुभाष प्रसाद और कोडरमा पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता विवेक कुमार शामिल थे। जांच टीम ने सड़क के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सड़क की वर्तमान स्थिति के साथ अलकतरा और गिट्टी की मोटाई तथा निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता और मानकों की जांच की। निरीक्षण के दौरान जहां भी निर्माण कार्य में कमियां या त्रुटियां पाई गईं, वहां संबंधित संवेदक और विभागीय कर्मियों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि स्थल निरीक्षण के आधार पर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। जांच के दौरान स्थानीय लोग दीपेश अग्रवाल, माले नेता धनंजय यादव, विक्रम यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण में यदि सरकारी राशि के दुरुपयोग या गुणवत्ता में लापरवाही की पुष्टि होती है तो संबंधित संवेदक और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस पर पौधरोपण कार्यक्रम

झुमरी तिलैया (कोडरमा): ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय के सभी स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर विभिन्न फलदार एवं औषधीय वाले पौधे लगाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला नोडल पदाधिकारी सौरभ शर्मा ने सभी प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों, कार्यों एवं महत्ता से अवगत कराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं में सेवा, अनुशासन, नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी एवं राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। स्वयंसेवकों का दायित्व है कि वे समाज की आवश्यकताओं को जाने. समझें और जनहित से जुड़े कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाएँ। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मोहित कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना प्रशिक्षुओं को शिक्षा के साथ समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों से अवगत कराती है। आज के युवा सुनहरे कल का मजबूत स्तंभ है । उन्होंने प्रशिक्षुओं को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, सामाजिक सेवा तथा जन. जागरूकता के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बीएड. सत्र 2025-27 के प्रशिक्षु बिनोद कुमार यादव, विश्वजीत राज, अंकित चंद्रा, लोकेश कुमार, पवन पंडित, सागर कुमार दास, राहुल कुमार, प्रभात कुमार यादव, कुंदन कुमार, दीपक कुमार, योगेंद्र साव, महेश कुमार महतो, सुशांत राज, मनोरंजन पाण्डेय, उर्मिला कुमारी, प्रिया कुमारी, उजाला कुमारी, नंदनी कुमारी एवं अन्य सहित महाविद्यालय के सभी सहायक प्राध्यापक डॉ. रामकृष्ण प्रसाद, डॉ. इंद्र कुमार जायसवाल, खुशबू कुमारी सिन्हा, संजीत कुमार, सीताराम यादव, चुन्नु कुमार, बिनीता कुमारी सहित अन्य शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे।

एमएमडीआर बिल के खिलाफ राजद का समाहरणालय के समक्ष दिया धरना

मेट्रो संवाददाता

कोडरमा : राष्ट्रीय जनता दल(राजद) झारखंड प्रदेश के आह्वान पर 24 सितंबर को जिला मुख्यालय कोडरमा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ विशाल धरना. प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोडरमा प्रखंड अध्यक्ष मो मुबारक ने किया, जबकि संचालन राजद युवा नेता दीपक यादव ने किया। धरना में बतौर मुख्य अतिथि संसदीय बोर्ड सदस्य सह कोडरमा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव और विशिष्ट अतिथि जिप अध्यक्ष रामधन यादव मुख्य रूप से शामिल रहें। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुभाष प्रसाद यादव ने संबोधित करते कहा कि केंद्र सरकार का यह नया संशोधन विधेयक पूरी तरह से जनविरोधी, आदिवासी. विरोधी और देश के संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है। झारखंड देश की खनिज संपदा का हृदय. स्थली है।राज्य की अर्थव्यवस्था,औद्योगिक विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं यहाँ के खनिजों व राजस्व पर टिकी हैं। किंतु केंद्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से

राज्यों के कर, सेस और खनिज अधिकारों को सीमित कर झारखंड की वित्तीय स्वायत्तता को कुचलने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिजों पर पहला अधिकार झारखंड का है, केंद्र सरकार एमएमडीआर बिल वापस नही ली तो झारखंड स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब बिल वापस लेने की मांग की। जिप अध्यक्ष रामधन यादव ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के अधिकारों पर डाका डालने वाले इस विधेयक को वापस नहीं लिया, तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झारखंड के लोगों के साथ अन्याय कर रही है।जनता में भारी आक्रोश है और उलगुलान करने को तैयार है। धरना को मनोज रजक,डॉ कमालुद्दीन, रामबचन यादव, संजय दास, विजय यादव, संतोष चन्द्रवंशी, शिवशंकर बर्णवाल, भीम यादव समेत राजद नेताओ ने संबोधित किया। धरना के पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल के नाम अपर समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा।
प्रमुख मांगेः-
1. विधेयक की वापसीः खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने वाले प्रावधानों को तुरंत वापस लिया जाए।
2. राजस्व व वित्तीय हितों की सुरक्षाः झारखंड के खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व पर राज्य के वैधानिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा हो।
3. पारंपरिक अधिकारों का संरक्षणः खनिज-युक्त भूमि पर कर और सेस लगाने के राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को यथावत रखा जाए।
4.आदिवासी-मूलवासी हितों की रक्षाः खनन क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों, मूलवासियों और विस्थापितों के जल, जंगल, जमीन व रोजगार के अधिकारों से कोई समझौता न हो।
5. स्थानीय युवाओं को प्राथमिकताः खनिज दोहन और उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में कानूनी रूप से प्राथमिकता दी जाए।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल,जिला इकाई कोडरमा के वरिष्ठ पदाधिकारी,प्रखंड अध्यक्ष कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे।

डिबडीह ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार पलटी, बाल-बाल बचे दो युवक

मेट्रो रेज

रांची : डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित डिबडीह ओवरब्रिज पर शुक्रवार की दोपहर एक बड़ा कार हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर पर चढ़ गई और फिर स्ट्रीट लाइट के खंभे को जोरदार टक्कर मारते हुए पुल के बीचों-बीच पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया।

तेज रफ्तार के कारण चालक ने खोया नियंत्रण: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। पुल के ऊपर अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी पहले डिवाइडर से जा टकराई और फिर स्ट्रीट लाइट के पोल को तोड़ते हुए सड़क पर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पोल क्षतिग्रस्त हो गया और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया।

कार में दो युवक थे सवार: गनीमत यह रही कि गाड़ी पलटने के बावजूद दोनों युवकों को गंभीर चोटें नहीं आईं और उन्हें मामूली खरोंचों के साथ सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

राहगीरों ने पलटी कार को सीधा कर युवकों को निकाला: घटना के तुरंत बाद सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने तत्परता और इंसानियत दिखाई। राहगीरों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद पलटी हुई कार को सीधा किया और दोनों घायल युवकों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार में मदद की। हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन और यातायात को सामान्य कराने में जुट गई।

संत जेवियर स्कूल की चलती बस पर गिरा पेड़, सभी बच्चे सुरक्षित

रांची : राजधानी समेत पूरे झारखंड में बीते 22 सितंबर से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज शुक्रवार को भी रांची में सुबह से तेज आंधी और बारिश हो रही है। इस बीच डोरंडा चौक स्थित एजी मोड़ के पास संत जेवियर स्कूल की अचानक चलती बस पर एक पेड़ गिर गया।

घटना के वक्त बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। हालांकि इस हादसे में किसी भी बच्चे या बस स्टाफ को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं।

जानकारी के अनुसार, डोरंडा स्थित संत जेवियर स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान एजी मोड़ के पास तेज आंधी के कारण सड़क किनारे लगा पेड़ अचानक बस के ऊपर जा गिरा। पेड़ गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए बस के ऊपर से पेड़ हटाने में मदद की। राहत की

बात रही कि पेड़ गिरने के बावजूद बस में सवार किसी भी बच्चे या स्टाफ को चोट नहीं आई।स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क से पेड़

अपर बाजार से 61 वर्षीय राजेश माहेश्वरी लापता, तलाश में जुटे परिजन

रांची: राजधानी रांची के अपर बाजार निवासी 61 वर्षीय राजेश माहेश्वरी 24 सितंबर की शाम से लापता हैं। जानकारी के अनुसार, वह शाम करीब 8 बजे अपने घर से बिना बताए निकले थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन अब तक उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले की सूचना कोतवाली थाना, रांची को दी गई है। पुलिस की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को राजेश माहेश्वरी के बारे में कोई जानकारी मिले या वह कहीं दिखाई दें, तो तत्काल कोतवाली थाना, रांची को इसकी सूचना दें।

स्पोर्टिफाई टी20 चैंपियनशिप का आगाज 29 सितंबर से

रांची: रांची में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और रोमांचक टी20 टूनार्मेंट का आगाज होने जा रहा है। स्पोर्टिफाई टी20 चैंपियनशिप का आयोजन 29 सितंबर से पिनेकल क्रिकेट एकेडमी, होचर में किया जाएगा।

इस टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्टिफाई इवेंट्स द्वारा किया जा रहा है, जिसके को-फाउंडर्स देवांश पोद्दार और स्नेह लोहिया हैं। प्रतियोगिता का आयोजन जमशेदपुर स्टीलर्स के सहयोग से किया जा रहा है, जो झारखंड टी20 के पहले संस्करण के उपविजेता रहे थे। जमशेदपुर स्टीलर्स की ओर से इस साझेदारी में टीम के उएड अभिनव सिंह राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

टूर्नामेंट को रांची स्पोर्ट्स एकेडमी का सहयोग प्राप्त है, जिसके सचिव एवं ठक्र कोच अनिसुर रहमान हैं।

इस चैंपियनशिप में रांची सहित झारखंड के अलग-अलग हिस्सों से कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक टी20 क्रिकेट खेलने और अपनी प्रतिभा को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। स्पोर्टिफाई टी20 चैंपियनशिप का उद्देश्य रांची और झारखंड के स्थानीय क्रिकेट को एक बेहतर मंच प्रदान करना है।

थाईलैंड के बौद्ध मंदिर की थीम पर बनेगा हटिया स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का भव्य पंडाल

मेट्रो रेज

रांची: हटिया स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का यह 62वां साल है । इस वर्ष समिति द्वारा थाईलैंड के बौद्ध मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा रहा है । इस पंडाल को दक्षिण-पूर्वी एशियाई वास्तुकला मुख्य रूप से थाईलैंड के बौद्ध मंदिर की थीम पर तैयार किया जा रहा है । इसकी बहु-स्तरीय छतें और नुकीले घुमावदार किनारे थाई शैली की पहचान हैं। इस विशाल ढांचे को बांस, कपड़े, लकड़ी और फाइबरग्लास जैसी अस्थायी सामग्रियों की मदद से तैयार किया जा रहा है,। बंगाल के 25 कारीगर इस पंडाल को बनाने में लगे हुए है ।

पंडाल की ऊंचाई 200 फीट एव चौड़ाई 150 फीट रहेगी । पंडाल के निर्माण में लगभग 11 लाख का खर्च है ।

समिति के सचिव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पंचमी के दिन पंडाल का उद्घाटन कर दिया जाएगा । उसी दिन डांडिया का भी आयोजन किया गया है । हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ।

समिति 2026 इस प्रकार है

संस्थापक - स्व.रण विजय कुमार सिंह,मुख्य संयोजक - संजू चौबे, सीके सिंह, आरएन यादव, आर एन मेहता,सह संयोजक- अनूप सिंह , शिव शंकर चैटर्जी, अरुण यादव ,मुख्य संरक्षक - प्रदीप गुप्ता, अजय साह,संजय सिंह सोनू, बिनु सिंह, मंजुल कैरकेटा, मनोज पांडेय, सतीश सिंह, प्रकाश सिंह, अर्चित आनंद, अंजनी सिंह, ललन सिंह

,संरक्षक - अवधेश सिंह, मिथिलेश कुमार पाण्डेय

नित्यालाल कुमार, अरुण सिंह, मनोज राय, उपेन मदार्ना, पार्थो चक्रवर्ती, अध्यक्ष - नंदन यादव,सचिव - इंद्रजीत सिंह,सह सचिव - अभिजीत हालदार, रवि राय, सौरव पांडेय (गोलू),कार्यकारी अध्यक्ष - अरुण बाउरी, रजनीश सिंह, संतोष यादव,

कोषाध्यक्ष - सोमनाथ बाउरी, चंदन यादव ,सहकोषाध्यक्ष - चंदन कुमार, अभिषेक कुमार (सुमित),अभिजीत बाउरी,वरीय उपाध्यक्ष - विश्वजीत सिंह, बिट्टू यादव, डॉ रजनी शर्मा, आरुषि वंदना, पी कृतिका राव, लवली गुप्ता, अंजलि सिन्हा, प्रथम चौबे,

राजू ठाकुर, धनंजय उपाध्याय, रितेश कुमार, दीपक राम, भोला यादव, मन्नू चौधरी, अरविंद यादव, आनंद शंकर , धनजय मिश्रा, दशरथ यादव, किशोर हरि, प्रभात मिश्रा, विशाल सरकार, प्रभात कुमार पाठक, मनीष वर्मा, संजय चौधरी, राजकुमार यादव, आकाश रजवार, विनीत साहू , निखिल यादव , श्याम कुमार ओझा ,उपाध्यक्ष - बैद्यनाथ मंडल, जीतू सिंह, बबलू कुमार, अजय सिंह, अजय राम, यमुना प्रसाद, शैलेन बाउरी, बीके प्रसाद,आयुष सिंह, अमन यादव, अमित पांडेय, पंकज हेला, अंकित सिंह, शिव कुमार, भावेश मिश्रा, शिवा राव, प्रखर शर्मा, अनिकेत सिंह, अभिषेक सिंह , विवेक कुमार, नवदीप कुमार, जितेन, नंद किशोर नंदू, मुकेश सिंह टुल्लू, राज कुमार,, आरव सन्नी, सुब्रतों भट्टाचार्य , शुभम यादव, राजेश कुमार , अमित कुमार , जितेन

सोनू बाउरी ,पंडाल सेक्शन - अरुण सिंह, अविनाश कुमार, गौतम बाउरी, गौतम हिनू, सुजय गहलोत, विशाल पांडेय,रवि यादव, सुलेंडर शर्मा, सौम्या गायन, राहुल गौड़, रवि शर्मा, अचिंता मरदाना, अभिषेक सिंह, दीनू, अमन यादव , अभय उपाध्याय, अजय यादव , भोग विभाग - पवन चौधरी, अभिषेक (बिल्लू), स्वराज बोस, सुनील सिंह, चंचल पासवान, आर ए कुशवाहा, सुनील साईं, ,महामंत्री - शुभम कुशवाहा, मनीष पंडित, सोनू कुजूर, सोनू कुमार, अभिजीत महतो, विक्की चौधरी, अरविंद महतो, साईं, शिवांश मिश्रा, रोहित महतो।

झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी यूजी-पीजी की सीटें, डॉक्टरों से लेकर संसाधनों तक होगा विस्तार

संवाददाता

रांची: राज्य के मेडिकल कॉलेजों में यूजी-पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। इन सीटों के साथ ही फैकल्टी, डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी अनुपात में बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा करते हुए सभी संस्थानों को यह बताने का निर्देश दिया कि उनके पास अभी कितने डॉक्टर और स्टाफ हैं, और अगले तीन सालों में उन्हें कितने की जरूरत होगी।

सीट बढ़ाने के साथ पदों का पुनर्गठन जरूरीः समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सीट बढ़ाने के साथ पदों का पुनर्गठन जरूरी है। फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए संविदा पर प्रोफेसरों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की सेवाएं लेने और दूसरे राज्यों से योग्य प्राध्यापकों को बुलाने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया गया।

एसएनएमएमसीएच धनबाद ने वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना में 250 यूजी और 200 पीजी सीट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं दुमका, हजारीबाग, पलामू समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी यूजी की 200 और पीजी की 150 सीटें तक बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया, जिससे यह प्रस्ताव और भी पुख्ता लगे।

बोकारो-चाईबासा में अगले वर्ष से पढ़ाई शुरू कराने का प्रयासः बोकारो और चाईबासा के निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेजों के भवन अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। निर्धारित संसाधन और मानक पूरे होने पर इन दोनों कॉलेजों में अगले वर्ष से पढ़ाई शुरू कराने की दिशा में प्रयास किया जायेगा।

बैठक में विशेष सचिव डॉ नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला और मेडिकल एजुकेशन निदेशक डॉ पी भट्टाचार्य समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

रांची विवि में पीएचडी में एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची जारी, इंटरव्यू जल्द

रांचीः रांची यूनिवर्सिटी (आरयू) ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2026-27 के इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। विवि की कुल 331 सीटों के लिए 567 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी उपलब्ध सीटों से 236 अधिक अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे।

कुलपति प्रो सरोज शर्मा के निर्देश और रिसर्च डायरेक्टर डॉ परवेज हसन की निगरानी में 150 से अधिक आपत्तियों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद यह सूची जारी की गई है। इस बार दाखिले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पीएचडी प्रवेश में पहली बार राज्य सरकार की आरक्षण नीति पूरी तरह लागू की जा रही है।

अंग्रेजी, हिंदी और भूगोल में बड़ी दावेदारीः मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में एक-एक सीट के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़ा मुकाबला अंग्रेजी (70), हिंदी (57), भूगोल (54), अर्थशास्त्र (36) और दर्शनशास्त्र (34) में होगा। इंटरव्यू की तिथियां घोषित करेगा विविः विवि प्रशासन जल्द ही विषयवार इंटरव्यू की तिथियां घोषित करेगा। साक्षात्कार मोरहाबादी स्थित संबंधित पीजी विभागों में होंगे। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण पत्र और उनकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी तैयार रखनी होगी।

क्या बदला : पूर्व में जारी सूची संशोधित हुई है। दावों के सत्यापन से 55 अभ्यर्थियों का साल खराब होने से बच गया।

आरक्षण नीति का असर : पहली बार राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर का अनुपालन होने से आरक्षित वर्ग (एसटी, एससी, ओबीसी व अन्य) के शोधार्थियों को निर्धारित कोटे के तहत उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।

क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा : कुडुख, नागपुरी, पंचपरगनिया, हो, खोरठा, कुड़माली, मुंडारी, खड़िया और संथाली जैसी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों को भी अपनी शोध प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है।

झारखंड के डॉक्टरों की रांची में 27 को बैठक, सुरक्षा व लंबित मांगों पर बनेगी रणनीति

रांची : झारखंड के डॉक्टरों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों की राज्य स्तरीय बैठक 27 सितंबर को रांची में होगी। बैठक सुबह 11:30 बजे क्टअ हॉल में आयोजित की जाएगी। इसमें डॉक्टरों की सुरक्षा, लंबे समय से लंबित मांगों और कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में झारखंड के सभी जिलों से चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के प्रतिनिधि, मेडिकल छात्र, महिला डॉक्टर और विभिन्न चिकित्सा संगठनों की जिला इकाइयों के प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे।

झारखण्ड सरकार कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पूर्व, राँची।
अति अल्पकालिन निविदा सूचना –51 / 2026–27

1) विभाग का नाम : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची ।
2) विज्ञापन दाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची पूर्व राँची ।
3) परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय : 1.10.2026 अपराह्न 5 बजे तक।
4) निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : 3.10.2026 अपराह्न 3:30 बजे तक।
5) निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 3.10.2026 अपराह्न 4 बजे।
6) परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान : 1) कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय,पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची पूर्व, राँची। 2) अधीक्षण अभियन्ता, का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता, राँची अंचल, राँची।
7) निविदा प्राप्ति का स्थान : 1) कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची पूर्व, राँची।
8) कार्य विवरणी :

क्र०	कार्य का नाम	प्रा० राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण वि० का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Day by day operation, maintenance and Smooth water supply in Government Building of Doranda under D.W. & Sanitation, Division Ranchi East, Ranchi (for the year 2026-27 Six Month 1.10.26 to 31.03.2027)	2437973.00	48800.00	5000.00	Six Months
2	Day by day maintenance of plumbing fixtures, cleaning of toilet and bathroom, MLA flats, Guest house and Jharkhand vidhan sabha pool quarters under D.W. & Sanitation, Division Ranchi East, Ranchi for the year 2026-27 (Six Month 1.10.26 to 31.03.2027)	2268415.00	45400.00	5000.00	Six Months
3	Day by day maintenance and operation of pump at project building, Engineering building & MLA Residence under D.W. & Sanitation, Division Ranchi East, Ranchi for the year 2026-27 (Six Month 1.10.26 to 31.03.2027)	1442652.00	28900.00	2500.00	Six Months
4	Operation & Maintenance of STP (MBBR Technology and Water treatment plant cum pump house, Swiming pool, Fountain at Residential complex for legistative member of Jharkhand Vidhan sabha situated at Kute, Dhurwa under D.W. & Sanitation, Division Ranchi East, Ranchi (for the year 2026-27 Six Month 1.10.26 to 31.03.27)	1892771.00	37900.00	5000.00	Six Months
5	Day by day maintenance for cleaning of toilet and bathroom and water supply at Hon'ble Judges Bunglow and other Jharkhand High court pool Quarters, Doranda under D.W. & Sanitation, Division Ranchi East, Ranchi for the year 2026-27 (Six Month 1.10.26 to 31.03.2027)	2376352.00	47600.00	5000.00	Six Months

आवश्यक शर्तों के लिए देखें www.jharkhand.gov.in
Email ID- eedwsd.ranchieast@gmail.com

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्व० प्र० राँची पूर्व राँची ।

PR 390390 Drinking Water and Sanitation(26-27)D

सूक्ति

सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर

विकास की रफ्तार के साथ जीवन की सहजता जरूरी

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स-2026 में उभरते हुए शहरों की सूची में भारत के 46 शहरों का होना बदलती आर्थिक तस्वीर का संकेत है। लंबे समय तक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलूरु जैसे महानगर ही देश की शहरी आर्थिक ताकत के प्रतीक रहे हैं। अब जयपुर, भोपाल, उदयपुर और सूरत जैसे शहर भी अपनी आर्थिक पहचान मजबूत कर रहे हैं। मजबूत जीडीपी, बढ़ता श्रमबल, उत्पादकता और आय में वृद्धि इस बदलाव की बुनियाद हैं। वर्ष २०५० तक दिल्ली के दुनिया की 63वीं सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान इसी रफ्तार की तस्वीर पेश करता है। इस सुनहरी तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि किसी शहर की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जरूरत इस बात की भी है कि वहां रहने वाले लोगों का जीवन सहज, सुरक्षित और स्वस्थ रहे। सवाल यही है कि क्या आर्थिक वृद्धि के साथ शहर बेहतर जीवन गुणवत्ता भी दे पाएंगे? भारत के शहरों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ आबादी और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है। प्रदूषण कई शहरों की स्थायी समस्या बन चुका है। भूजल का स्तर गिर रहा है। लोगों के लिए पर्याप्त और किफायती आवास उपलब्ध कराना चुनौती है। सार्वजनिक परिवहन की क्षमता सीमित है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ता है। कचरा निस्तारण और सीवेज प्रबंधन की कमजोर व्यवस्थाएं भी शहरों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बोझ डाल रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शहरों का विस्तार अक्सर नियोजन की गति से तेज होगा है। पहले आबादी आती है, फिर सड़क, पानी, सीवर, परिवहन और आवास जैसी सुविधाओं की योजना बनाई जाती है। नतीजा यह होता है कि आर्थिक विकास तो दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ अव्यवस्था भी बढ़ती जाती है। ऐसे में देश को अब 'तेजी से बढ़ते शहर' नहीं, बल्कि 'रहने योग्य शहर' बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। शहरों की आर्थिक योजनाओं को जल उपलब्धता, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास और कचरा प्रबंधन जैसी दक्षता से जोड़ना होगा। इन व्यवस्थाओं को आबादी के बसने से पहले सुनिश्चित करना होगा। भारत के छोटे और मध्यम शहरों के उभरने का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि विकास का दबाव कुछ महानगरों तक सीमित न रहे।

आर्थिक विकास जरूरी है, क्योंकि उसके बिना रोजगार और समृद्धि संभव नहीं। लेकिन ऐसा विकास भी अधूरा है जो लोगों की आय बढ़ाए और उनके जीवन की गुणवत्ता घटा दे। भारत के उभरते शहरों के सामने अब यही परीक्षा है कि वे केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बनेंगे या ऐसे शहर भी बनेंगे जहां लोग बेहतर कमाई के साथ बेहतर जीवन भी जी सकें। क्योंकि सफल होने के लिए विकास की रफ्तार के साथ-साथ जीवन की सहजता भी जरूरी है।

तकनीक के इस्तेमाल में मानवता की भी हो चिंता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आज दुनिया का सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। इसलिए नहीं कि आने वाले दौर में मानव जीवन को पूरी तरह बदल देगा, बल्कि इस बहस के लिए कि इसके फायदे ज्यादा हैं अथवा नुकसान। यों तो हर तकनीक अपने साथ कुछ नया लेकर आती है और उस पर बहस भी अपने तरीके से चलती है। दुनिया में जब कम्प्यूटर आया तो उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क रखने वालों की संख्या कम नहीं थी। अब, एआइ के पक्ष और विपक्ष में बोलने वालों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। अमरीकी राष्ट्रपति एआइ पर लगाम के पक्ष में तो नहीं है लेकिन उनकी चिंता इस क्षेत्र में चीन से आगे रहने की जरूर है। आइआइएससी बैंगलोर के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रतोश एपी की स्पष्ट मान्यता है कि एआइ से तरक्की तो होगी लेकिन सवाल यह कि इससे खुश कौन रहेगा।

दुनिया की बड़ी पांच एआइ कंपनियों में शुमार एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोदेई ने एआइ विकास की रफ्तार पर लगाम लगाने का समर्थन किया है। एमोदेई की सलाह का समर्थन एक्स एआइ कंपनी के मालिक एलन मस्क और ओपन एआइ के ऑल्टमैन ने भी किया है। मतलब साफ है कि दुनिया के शीर्ष उद्योगपति एआइ के पक्ष में तो हैं लेकिन उसकी रफ्तार को एक सीमा में बांधे रखना चाहते हैं। एआइ के फायदे-नुकसान की कशमकश में आम आदमी अब भी उधेड़बुन में है कि आखिर एआइ का भविष्य क्या होगा। उसकी चिंता इस बात को लेकर अधिक है कि एक तरफ उसकी रफ्तार कम रखने की बात करने वाले लोग भी उसके विकास पर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। वर्ष 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जेफ्री हिंटन भी एआइ से मानवता के खत्म होने की आशंका जता चुके हैं। देखा जाए तो एआइ को लेकर भ्रम फैलाने के काम में वे कंपनियां आगे हैं, जो इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती हैं। ओपन एआइ, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां उसकी सुरक्षा पर तो बात करती हैं लेकिन उसकी असली चिंता ये भी है कि उन्होंने अगर सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया तो कहीं एआइ की दौड़ में पिछड़ न जाएं। दुनिया के अनेक देश एआइ कंपनियों पर अघोषित नियंत्रण को लेकर भी काम कर रहे हैं। सरकारें एआइ पर बाध्यकारी कानून लाने से यह कहकर बचना चाहती हैं कि कंपनियां खुद अपनी लक्ष्मण रेखा तय करें। अभी इस चिंता का जवाब भी मिलना बाकी है कि क्या एआइ आने वाले दौर में उस इंसान से आगे निकल जाएगा जिसने उसे बनाया है। चिंता इस बात की भी है कि क्या एक दिन एआइ इंसानों पर भी नियंत्रण हासिल कर लेगा। यही, चिंता एआइ की रफ्तार धीमी रखने पर जोर दे रही है। नई दुनिया बनाने के चक्कर में दुनिया का चक्र डांवाडोल न हो जाए। नई तकनीक का स्वागत है लेकिन आगे निकलने की होड़ में मानवता को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान सभी को रखना होगा।

क्या कल्याणकारी से पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा भारत?

'ताजा उदाहरण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) का है। 15 अक्टूबर से दो हजार रुपए से अधिक के कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआइ लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा। सामान्य श्रेणी में यह शुल्क 300 रुपए तक सीमित रहेगा। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल जैसी कुछ श्रेणियों में दो हजार रुपए से अधिक के लेन-देन पर पांच रुपए का फ्लैट एमडीआर तय किया गया है। हालांकि, यह शुल्क सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा और पर्सन-टू-पर्सन यूपीआइ लेन-देन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। फिर सवाल यह है कि जब एक सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने और चलाने की लागत बढ़ती है तो उसका भुगतान किस मॉडल से होगा?'

विजय गर्ग

क्या भारत एक कल्याणकारी राज्य से 'कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट स्टेट' बनता जा रहा है? यह सवाल अभी शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन यह पूछने का आधार जरूर बन रहा है कि क्या सार्वजनिक सेवाओं में बाजार और शुल्क आधारित व्यवस्था का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है? क्या सरकार की भूमिका नागरिकों को सस्ती और सार्वभौमिक सुविधाएं देने से बदलकर ऐसी व्यवस्था बनाने की ओर बढ़ रही है, जिसमें सेवाओं की कीमत चुकाना नागरिक की जिम्मेदारी बनती जा रही है? यह बहस किसी एक फैसले से पैदा नहीं हुई है। रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक, पब्लिक प्रॉपर्टीज के मोनेटाइजेशन से लेकर डिजिटल पेमेंट तक और स्वास्थ्य से लेकर बिजली वितरण तक, सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका के बीच की रेखा बदल रही है। इसे केवल निजीकरण कहना भी सही नहीं होगा, पर यह सवाल महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव की कीमत आखिर कौन चुका रहा है?

ताजा उदाहरण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) का है। 15 अक्टूबर से दो हजार रुपए से अधिक के कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआइ लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होगा। सामान्य श्रेणी में यह शुल्क 300 रुपए तक सीमित रहेगा। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल जैसी कुछ श्रेणियों में दो हजार रुपए से अधिक के लेन-देन पर पांच रुपए का फ्लैट एमडीआर तय किया गया है। हालांकि, यह शुल्क सीधे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा और पर्सन-टू-पर्सन यूपीआइ लेन-देन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। फिर सवाल यह है कि जब एक सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने और चलाने की लागत बढ़ती है तो उसका भुगतान किस मॉडल से होगा? क्या हर पब्लिक सर्विस को अंततः किसी न किसी शुल्क के जरिये चलाना होगा? अगर शुल्क व्यापारी पर लगता है तो क्या उसका असर आगे चलकर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर नहीं पड़ सकता?

यही वह बिंदु है, जहां कल्याणकारी राज्य और बाजार आधारित राज्य की बहस शुरू होती है। दरअसल, भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ी है। यह अपने आप में गलत नहीं है। निजी निवेश से पूंजी आती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और कई सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधर सकती है। समस्या तब पैदा होती है, जब ऐसी सेवाएं भी केवल भुगतान करने की क्षमता से जुड़ने लगें, जिनका सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) इसका बड़ा उदाहरण है। पहली एनएमपी में वर्ष 2021-25 के दौरान लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज के मोनेटाइजेशन का अनुमान था। अब एनएमपी 2.0 के तहत 2026-2030 के बीच 16.72 लाख करोड़ रुपए की मोनेटाइजेशन क्षमता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 5.8 लाख करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र का निवेश शामिल है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मोनेटाइजेशन का अर्थ हमेशा सरकारी संपत्ति बेच देना नहीं है। इसमें लंबे समय की लीज, कंसेशन व पीपीपी जैसे मॉडल भी शामिल होते हैं, यानी स्वामित्व सरकार के पास रह सकता है, पर उससे होने वाली आय व इस्तेमाल का ढांचा बदल जाता है। असली सवाल 'निजी हाथ' में जाने का ही नहीं, बल्कि नेशनल प्रॉपर्टी से मिलने वाली सुविधा की कीमत व उसकी पहुंच का है। रेलवे इसका संवेदनशील उदाहरण है। कोविड से पहले सीनियर सिटीजन को किराये में रियायत मिलती थी। पुरुष यात्रियों को चालीस प्रतिशत और महिला यात्रियों को पचास प्रतिशत तक की छूट थी। मार्च 2020 में यह रियायत बंद हुई और अब तक सामान्य रूप से बहाल नहीं की गई है।

एयरपोर्ट्स के विकास में निजी निवेश ने एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बदला है, लेकिन इसके साथ यात्री शुल्क का सवाल भी जुड़ा है। कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में होती है। अस्पताल निजी हो या सरकारी, नागरिक के लिए बीमारी का खर्च सबसे बड़ा आर्थिक जोखिम बन सकता है। भारत में स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च पिछले वर्षों में घटा है। वर्ष 2021-22 में भी निजी अस्पतालों का स्वास्थ्य खर्च में हिस्सा लगभग 26.96 प्रतिशत था और भारत के कुल स्वास्थ्य खर्च में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च की हिस्सेदारी लगभग 47 प्रतिशत आंकी गई है। बैंकिंग में मिनिमम बैलेंस, एटीएम ट्रांजैक्शन, एसएमएस जैसी सेवाओं पर शुल्क वसूली की बहस होती रही है। इससे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या बैंकिंग व्यवस्था को सार्वभौमिक बनाने के बाद उसकी छोटी-छोटी लागत भी नागरिक पर डालना उचित है? यूपीआइ शुल्क भी इसी बहस को आगे बढ़ाता है। अगर डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है तो उसके संचालन की लागत कौन वहन करे- सरकार, बैंक, पेमेंट कंपनियां या व्यापारी? इसका कोई आसान उत्तर नहीं है पर यह तय करना जरूरी है कि लागत का अंतिम बोझ उपभोक्ता तक न पहुंचे।

भारत को शायद 'कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट स्टेट' कहने से पहले यह देखना होगा कि सरकार बाजार को कितना स्थान देती है। नागरिक के हित के लिए कितनी मजबूत नियामक तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करती है। आखिरकार किसी भी आर्थिक मॉडल की सफलता का पैमाना केवल जीडीपी, निवेश या निजी पूंजी नहीं हो सकता। असली कसौटी यह है कि एक सामान्य नागरिक को शिक्षा, इलाज आदि के लिए अपनी आय का कितना हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है। विकास तब ही कल्याणकारी कहलाएगा, जब बाजार बढ़े तो अवसर बढ़ें, लेकिन नागरिक की जेब पर अनिवार्य सेवाओं का बोझ लगातार न बढ़े। यही वह सीमा है, जहां से भारत के भविष्य के आर्थिक मॉडल पर असली बहस शुरू होती है।

अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों?

'हालांकि मुक्त व्यापार समझौतों के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है और उसके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। असमानता के मुद्दे पर देखें तो भारत में गरीबी घटी है, लेकिन संपत्ति और आय का अंतर बढ़ा है। यह केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर की समस्या है। इसका एक प्रमुख कारण लेबर सप्लाई बढ़ना है जिसके चलते मजदूरी नहीं बढ़ी है। हमें समझना होगा कि एआई और नई तकनीकें जीडीपी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर विकास का लाभ व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचता, तो केवल ऊंची वृद्धि दर पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पर यही भारतीय अर्थव्यवस्था का सच है ।'

डा. वरिंदर भाटिया

हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आने के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जीडीपी की गणना की प्रक्रिया को लेकर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इसका यह भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि कौनसे क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौनसा क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। इस साल अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी, जो ब्लूमबर्ग और आरबीआई के अनुमानों से अधिक है। सरकार इसे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, जो ठीक है, हालांकि इन आंकड़ों पर सरकार में ही वित्त सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग ने सवाल उठाए, जिसने बहस छेड़ दी। फिर कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कहा है कि पिछले साल के जीडीपी आंकड़ों में संशोधन के कारण मौजूदा विकास दर वास्तविकता से अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है या फिर जीडीपी के आंकड़ों की तस्वीर उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। यह विवाद मुख्य रूप से जीडीपी की तुलना के आधार यानी फेस ईयर डेटा को लेकर है। अगर सरकार कह रही है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि अप्रैल से जून की मौजूदा तिमाही में भारत का कुल आर्थिक उत्पादन पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 7.8 फीसदी अधिक रहा। ये तिमाही के आंकड़े दरअसल एक अनुमान हैं। ये ग्रोथ का सटीक आकलन नहीं होता।

यह अनुमान इसलिए जारी होते हैं ताकि उसके हिसाब से बजट बने, पूरे देश में सालभर में हुई कमाई का असली आकलन करने में एक-डेढ़ साल लग जाता है। इस मुद्दे पर सवाल है कि अगर पिछले वर्ष का आधार आंकड़ा बदल गया है, तो नई वृद्धि दर को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि समय-समय पर आंकड़ों की गणना की पद्धति और आधार वर्ष बदलते रहते हैं, इसलिए संशोधित सिरीज के आधार पर ही तुलना उचित मानी जाती है। यह एक ठोस कारण है। हर सरकार अपने कार्यकाल में जीडीपी की गणना के मैथड और बेस ईयर को अपडेट करती है ताकि अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर बेहतर ढंग से सामने आ सके। ऐसा दुनियाभर में होता है। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो ये सभी चीजें भी बेहतर होंगी। लेकिन समस्या यह है कि पिछले 15 साल के दौरान भारत में जीडीपी लगातार बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति जीडीपी भी बढ़ी है। इसके बावजूद रोजगार में वैसी बढ़ोतरी नहीं दिखी। और आम श्रमिकों और नियमित मजदूरी पर काम करने वाले लोगों की आय भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। यह एक रिसर्च और खोज का बिन्दु है। भारत में जितनी भी वृद्धि हुई है, उससे यह साफ दिखाई देता है कि उसमें असमानता की बड़ी भूमिका है। पहले से संपन्न लोगों तक जीडीपी वृद्धि का बड़ा हिस्सा पहुंच रहा है, जिनके पास पहले से पूंजी और संसाधन हैं, लाभ मुख्य रूप से उन्हीं के पास केंद्रित होता जा रहा है। इसके विपरीत, आम जनता, मजदूरों और किसानों तक उस वृद्धि का लाभ उसी अनुपात में नहीं पहुंच रहा। अमीरों के पास धन जाने से उसका लाभ अपने आप सभी तक पहुंच जाने से जुड़ा ट्रिकल-डाउन सिद्धांत व्यावहारिक रूप से सफल नहीं रहा है। इसके लिए मजदूरों और किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर अधिक निवेश करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है रोजगार और मजदूरी बढ़ाना, क्योंकि इससे लोगों की खरीद क्षमता और घरेलू मांग बढ़ती है। सरकार को वैश्विक चुनौतियों, जैसे युद्ध और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में संतुलन भी बनाना पड़ता है। उस व्यवस्था में बदलाव करना होगा जिसमें आर्थिक विकास का सबसे ज्यादा लाभ पहले से संपन्न लोगों को मिलता है। इसके बजाय मजदूरों, वेतनभोगी कर्मचारियों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नियमों और नीतियों में बदलाव किए जाएं। साथ ही सरकार बड़े पूंजीपतियों और अधिक संपन्न वर्ग पर टैक्स लगाकर उस संसाधन का उपयोग बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर करे। इन क्षेत्रों में निवेश करने से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी पैदा होगा। इससे लोगों के हाथ में पैसा आता है, मांग बढ़ती है और जीवन स्टार बेहतर होता है। घरेलू स्तर पर मांग बढ़ाने से ही विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कई मायनों में नाजुक स्थिति में है और यह बात दुनिया भर के निवेशक भी समझते हैं। देश के बड़े उद्योगपति खुद पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि देश के भीतर मांग पर्याप्त नहीं है। अगर हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले घरेलू मांग बढ़ानी होगी। और मांग तब बढ़ती है जब लोगों के पास रोजगार हो और उनकी आय बढ़े। इसलिए रोजगार और वेतन वृद्धि, दोनों ही न केवल देश के अंदरूनी आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि वैश्विक निवेशकों के भरोसे के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप व्यापक आर्थिक संकेतकों को देखें, तो विकास दर मजबूत है। राजकोषीय स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर है और कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी पहले के मुकाबले काफी मजबूत दिखाई देती है। हालांकि मुक्त व्यापार समझौतों के बाद एक नया दौर शुरू हो रहा है और उसके लिए हमें बेहतर तैयारी करनी होगी। असमानता के मुद्दे पर देखें तो भारत में गरीबी घटी है, लेकिन संपत्ति और आय का अंतर बढ़ा है। यह केवल भारत नहीं, बल्कि दुनिया भर की समस्या है। इसका एक प्रमुख कारण लेबर सप्लाई बढ़ना है जिसके चलते मजदूरी नहीं बढ़ी है। हमें समझना होगा कि एआई और नई तकनीकें जीडीपी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर विकास का लाभ व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचता, तो केवल ऊंची वृद्धि दर पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है, पर यह ही भारतीय अर्थव्यवस्था का काला सच है। असली विकास तब होगा, जब गरीब और अमीर के बीच आय अंतर बहुत कम हो जाएगा।

जीवन की अभिव्यक्ति

ओशो

सिद्गुरु जग्गी वासुदेव

मैं बस यह जानना चाहता हूं कि श्राद्ध का क्या महत्त्व है। सद्गुरु- अगर आप शव को दो-तीन दिन से ज्यादा रखें, तो आप देखेंगे कि उसके शरीर के बाल बढ़ने लगते हैं। अगर कोई इनसान शेविंग करता है, तभी आपका ध्यान इस पर जाएगा क्योंकि चेहरे के बालों पर ध्यान ज्यादा जाता है। उसके नाखून भी बढ़ने लगेंगे। इसकी वजह जीवन की अलग-अलग रूपों में होने वाली अभिव्यक्ति में है। मैं इसे अलग करके समझाता हूं, एक जीवन होता है और एक भौतिक या स्थूल जीवन होता है। भौतिक जीवन खुद को व्यक्त करता है। भौतिक जीवनी ऊर्जा, जिसे आम तौर पर प्राण कहा जाता है की पांच मूल अभिव्यक्तियां हैं। वैसे तो उसकी दस अभिव्यक्ति हैं लेकिन उससे चीजें और जटिल हो जाएंगी, तो पांच मूल अभिव्यक्ति हैं। प्राणों के अलग-अलग प्रकार इन्हें समान, प्राण, उडान, अपान और व्यान कहा जाता है। जब किसी इनसान को मृत घोषित किया जाता है, तो अगले इक्कीस से चौबीस मिनट में, समान शरीर से बाहर निकलने लगेगा। समान शरीर के तापमान को ठीक रखता है। इसीलिए सबसे पहले शरीर ठंडा होने लगता है। कोई मर गया है या जिंदा है, यह जांचने का पारंपरिक तरीका है कि नाक छूकर देखा जाता है। अगर नाक ठंडी हो गई है, तो इसका मतलब है कि वह इनसान मर चुका है। अड़तालीस से चौंसठ मिनट के बीच प्राण शरीर से निकल जाता है। उसके बाद छह से बारह घंटे के बीच, उडान निकल जाता है। उडान के शरीर से निकलने तक कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं से शरीर को पुनर्जीवित किया जा सकता है। एक बार उडान के बाहर निकलने के बाद शरीर को फिर से पुनर्जीवित करना असंभव है। अगली चीज होती है अपान जो आठ से अठारह घंटों के भीतर निकलती है। उसके बाद व्यान, जो प्राण की रक्षक प्रवृत्ति है, शरीर से निकलती है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में यह ग्यारह से चौदह दिनों के भीतर शरीर से बाहर जा सकती है। सामान्य मृत्यु का मतलब है कि मृत्यु वृद्धावस्था में हुई, जीवन के क्षीण होने से वे शरीर से निकल गए। अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना में होती है या दूसरे शब्दों में जीवन के जीवंत रहने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं होता है, शरीर अब भी बचा रहता है, तो उस जीवन का कंपन अड़तालीस से नब्बे दिनों तक जारी रहता है।

चिंतन-मनन

आपके पत्र

भारत की बेमिसाल धरोहर है आयुर्वेद

हमारे देश में 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम है स्वास्थ्यवर्धक भविष्य के लिए आयुर्वेद। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। और इसके महत्व दुनिया को बताना भी है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की शुरूआत की थी। जब दुनिया भर में वैश्विक महामारी ने कहर मचाया हुआ था, तब भी और अब भी हमारे देश के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों ने हमारे देश की इस धरोहर को अपना कर अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया और अब भी कर रहे हैं। आयुर्वेदिक पद्धति को दुनिया में एक नया आयाम मिला है।

आरती वर्मा,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।

प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website :** www.metrorays.in

email : metrorays.ranchi@gmail.com

न्यूज IN ब्रीफ

2003 के हत्या मामले का स्थायी वारंटी गुड्डू कुमार गिरफ्तार भेजा जेल

साहिबगंज : जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिरवाबाड़ी निवासी गुड्डू कुमार साह, पिता विजय साह के रूप में हुई है पुलिस के अनुसार गुड्डू कुमार साह के विरुद्ध जिरवाबाड़ी थाना में वर्ष 2003 में हत्या से संबंधित कांड संख्या 103/2003 दर्ज किया गया था। उक्त मामले में वह स्थायी वारंटी था और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था।पुलिस ने वारंटी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस की ओर से फरार व स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान जारी है।

जमशेदपुर सड़क हादसे में चार बच्चों की मौत पर डॉ.मुन्नम संजय ने जताया गहरा शोक

साहिबगंज : जमशेदपुर के दोमुहानी मोड़ के समीप गुरुवार की सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह समेत चार बच्चों की असामयिक मौत पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव देवघर जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और साहिबगंज कांग्रेस जिला प्रभारी डॉ.मुन्नम संजय ने गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त की है।डॉ.मुन्नम संजय ने कहा कि यह हृदयविदारक घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है।इतनी कम उम्र में चार मासूम बच्चों का असमय दुनिया से चले जाना अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि एक माँ की गोद उजड़ने का दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।संतान को खोने की पीड़ा ऐसी होती है ।जिसकी भरपाई जीवन में कभी संभव नहीं है।डॉ.मुन्नम संजय ने बताया कि उन्होंने देवघर एयरपोर्ट पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा इस अत्यंत कठिन और दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का भरोसा दिया।उन्होंने कहा कि इस हादसे में तृषा सिंह के साथ जान गंवाने वाले अन्य तीन बच्चों के परिवारों का दुःख भी उतना ही गहरा और असहनीय है।वह सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं।डॉ.मुन्नम संजय ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। दीपिका पांडेय सिंह सहित सभी शोकाकुल परिजनों को इस अपूरणीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

बिल्डिंग शाखा में 72 लॉकर काटकर करोड़ों रुपये की सोना चोरी की घटना को दिया था अंजाम

साहिबगंज/बरहरवा : अंतराज्जीय सोना चोर गिरोह के एक आरोपी हसन चिकना को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की ईटाहार पुलिस ने गुरुवार की सुबह मालदा डिविजन के बरहरवा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया हैं बताया जा रहा हैं कि आरोपी हसन चिकना राजधानी रांची से सोना की डिलेवरी करने के बाद वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन से बरहरवा आ रहा था। जिसकी भनक पुलिस को पहले से हो गई थी जिसके बाद उत्तर दिनाजपुर जिले की ईटाहार पुलिस ने बरहरवा जीआरपी के सहयोग से ट्रेन आने के पूर्व से ही सादे लिबास में स्टेशन परिसर में निगरानी करने लगे। जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अभिषेक साह कर रहे थे। जैसे ही गुरुवार की सुबह वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन बरहरवा स्टेशन पंहुची तो पुलिस की तैनाती की अभास होने पर हसन चिकना भागने के फिराक में था लेकिन पुलिस ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक उसके पास से लगभग 5 किलो के आसपास सोना बरामद किया गया हैं। हालांकि बरामद सोने की वास्तविक मात्रा और उसकी कीमत की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गयी है। गिरफ्तारी के बाद उसे जीआरपी रेल थाना लाया गया जहं से आवश्यक कागजी कारवाई पुरा करने के बाद उत्तर दिनाजपुर पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई।पुलिस सूत्रो के अनुसार हसन चिकना ईटाहार थाना कांड संख्या 339/26 में पुलिस का वांछित आरोपी था।इसी मामले में उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस के अनुसार हसन चिकना का नाम विभिन्न राज्यों में हुई सोना चोरी की घटनाओं से जुड़ा बताया जाता है। बरहरवा के माधोपाड़ा और राधानगर थाना क्षेत्र के पियारपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी उसके ठिकाने होने की जानकारी पुलिस को मिली है. पिछले 2017 में बोकारो स्थित एसबीआई बैंक में हुई चोरी के एक मामले में भी उसके आरोपी होने की बात पुलिस ने कही है।उस समय वह अपने साथियों के साथ बोकारो एसबीआई की नया मोड़ एडीएम विलडिग शाखा में 72 लॉकर काटकर कारोड़ो रुपये की सोना चोरी की घटना को अंजाम दिया था जिसके बाद उसे पुलिस ने मुबंई से गिरफ्तार भी किया था।

पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता : बजरंगी

साहिबगंज : भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह छत्तीसगढ़ प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार कई योजनाएं चला रही है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से वर्ष 2019 से अब तक देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है।बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि इससे किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिल रही है।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय और कृषि व्यवस्था को मजबूत करना है।

यूपी का सह-प्रभारी बनाए जाने पर अनंत ओझा का भव्य अभिनंदन भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया भरोसा

संवाददाता

साहिबगंज : राजमहल के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत ओझा को उत्तर प्रदेश का सह-प्रभारी बनाए जाने के बाद साहिबगंज भाजपा में उत्साह का माहौल है।इसी क्रम में गुरुवार को उत्सव बैंक्वेट हॉल में भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम कुमार यादव के नेतृत्व में भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर अनंत ओझा का अभिनंदन किया गया।समारोह में जिलेभर से पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं ने गुलदस्ता एवं शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।इस दौरान कार्यकताओं ने नई जिम्मेदारी के लिए अनंत ओझा को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।कार्यकताओं ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर उनके संगठनात्मक अनुभव और कार्यक्षमता पर भरोसा जताया है।उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिलना उनके राजनीतिक एवं संगठनात्मक अनुभव के प्रति पार्टी के विश्वास को दशार्ता है।इस अवसर पर अनंत ओझा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है,वह

उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है।वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकताओं की मेहनत और संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है।उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकताओं के साथ समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी क्षमता से कार्य करेंगे।सम्मान समारोह के दौरान कार्यकताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।उपस्थित भाजपा नेताओं एवं कार्यकताओं ने अनंत ओझा के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी नई जिम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर भाजपा के कुसुमाकर तिवारी,चंद्रभान शर्मा,रामानंद साह,प्रेमलाल मंडल उर्फ मंटा मंडल,मनोज यादव,अनुराग राहुल,विनोद चौधरी,जिला प्रभारी अमृत पांडे,सलखु सोरेन,धनंजय मंडल,प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश प्रसाद तिवारी,धर्मेंद्र कुमार, नमामि गंगे प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक राजेश मंडल,मत्स्य प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक राजीव चौधरी,पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वनाथ साह,रामदरश यादव श्यामल दास सहित विभिन्न पदाधिकारी,कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे।

साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण में देरी पर आजसू ने दिया धरना

संवाददाता

साहिबगंज : साहिबगंज-मनिहारी के बीच गंगा नदी पर बन रहे बहुप्रतीक्षित गंगा पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर गुरुवार को आजसू पार्टी ने महादेवगंज में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया।धरना का नेतृत्व जिलाध्यक्ष चतुरानंद पांडेय ने किया।आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडेय ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पुल निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध किया है।पत्र में कहा गया है कि साहिबगंज एवं मनिहारी के बीच गंगा नदी पर निमार्णाधीन यह पुल अत्यंत महत्वपूर्ण है।यह पुल झारखंड एवं बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल है।इसके पूर्ण होने से साहिबगंज, मनिहारी तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों का आवागमन बेहतर होगा,व्यापार,रोजगार,शिक्षा स्वास्थ्य एवं क्षेत्रीय गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।पत्र में उल्लेख है कि निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी को लेकर साहिबगंज की जनता में काफी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त हो रही है।आम जनता लंबे समय से इस महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही है।ऐसी स्थिति में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा कराकर संबंधित निर्माण एजेंसी एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।आजसू जिला अध्यक्ष ने मंत्री से अनुरोध किया है कि संबंधित विभाग एवं एजेंसी को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें तथा निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पुल नहीं,बल्कि समस्त साहिबगंज की जनता की अपील है।इस पुल के शीघ्र पूर्ण होने से लोगों का आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा।मौके पर सुनैना देवी, सुशीला देवी,रजनी देवी,प्रीति देवी, भीम नारायण दास,रामप्रवेश महतो, दीप नारायण सिंह,ओम कुमार,सूरज कुमार पंडित आदि मौजूद थे।

फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार

कर्मा पर्व मना रही महिलाओं के साथ कथित छेड़खानी

संवाददाता

साहिबगंज : मिजाचौकी थाना क्षेत्र के तेलियाडीह करमटोला रेलवे स्टेशन के समीप कर्मा पर्व मना रही महिलाओं के साथ कथित छेड़खानी और फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है।जहां गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण रिखियासन और रामकुमार राय के रूप में हुई है।उधर पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा और एक खोखा बरामद करने की बात कही है। पुलिस के अनुसार कर्मा पर्व के दौरान महिलाएं कार्यक्रम में शामिल थीं इसी दौरान दोनों युवक वहां पहुंचे और महिलाओं के साथ कथित तौर पर

छेड़खानी करने लगे।जहां महिलाओं द्वारा विरोध किए जाने पर आरोप है कि करण रिखियासन ने अपने जूते में छिपाकर रखा देशी कट्टा निकाला और फायरिंग कर दी।जहां गोली चलने की आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई।उधर इसघटना के बाद मोनिका देवी,पति रंजीत राम,ने मिजाचौकी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई।जहां शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।उधर पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों के पास से देशी कट्टा और एक खोखा बरामद किया गया।इस छापेमारी दल में मिजाचौकी थाना प्रभारी रूपेश कुमार यादव समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे।वही पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी।जहां पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

तीनपहाड़ में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने रैयत को दिलाया जमीन पर कब्जा

संवाददाता

साहिबगंज : राजमहल सिविल कोर्ट के वरिष्ठ सिविल जज डिवीजन क्क्क्क की अदालत के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से संबंधित रेयत को जमीन पर कब्जा दिलाया गया।मामला एकजीक्यूशन केस संख्या 25/2023 एवं मूल वाद संख्या 78/2014 से संबंधित है।अदालती दस्तावेज के अनुसार मामले में जैगुन निस्सा,पति स्व.हाजी हकीक शेख, निवासी तीनपहाड़ वादी हैं, जबकि अनवार अली,अख्तर अली, टिंकू अली,रिंकू अली,चांदनी बीबी,

अनिस अली,हसीम अली,अमीक अली सहित अन्य लोग प्रतिवादी बनाए गए थे।अदालत की ओर से जारी आदेश में संबंधित बेलीफ को डिक्रीधारी को संबंधित संपत्ति का कब्जा दिलाने का निर्देश दिया गया था।आदेश के अनुपालन में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए रेयत को जमीन पर कब्जा दिलाया गया।दस्तावेज में संबंधित भूमि का विवरण जिला साहिबगंज,अंचल राजमहल,थाना राजमहल, मौजा तीनपहाड़, जेबी नंबर-02 एवं प्लॉट नंबर-54 के रूप में दर्ज है।भूमि की सीमा में उत्तर दिशा में मस्जिद तथा दक्षिण दिशा में यूसुफ मियां का उल्लेख किया गया है।प्रशासन की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई। मामले से संबंधित अन्य दावे या आपत्तियां होने पर संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने के बाद ही उनका उल्लेख किया जा सकेगा।

खनन और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में राजद ने दिया धरना

केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

संवाददाता

साहिबगंज : खनन और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल राजद साहिबगंज जिला कमेटी की ओर से गुरुवार को रेलवे स्टेशन चौक के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राजद जिलाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने किया।इस दौरान राजद कार्यकताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधेयक को वापस लेने की मांग की।धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राजद जिलाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने कहा कि केंद्र सरकार खनिज संपदा से जुड़े कानूनों में संशोधन कर देश के प्राकृतिक संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि झारखंड सहित देश के आदिवासी एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के

हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए। राजद जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी जनहित और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाती रहेगी।वहीं,युवा राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने विधेयक को ह्लकाला कानूनह्व बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने के बाद अब देश के खनिज संसाधनों पर भी निजी हितों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है।उन्होंने कहा कि राजद इस विधेयक का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगा।सद्दाम हुसैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार विधेयक को वापस नहीं लेती है।तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा।उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा।इस मौके पर राजद जित्ता अध्यक्ष सत्यनारायण यादव,सचिव मुन्ना यादव,युवा जिला मो सद्दाम हुसैन,नगर अध्यक्ष दिनेश पासवान,मो० आवुल हुसैन,रामावतार सिंह,मामलेत शेख,जलपा हे मब्रम,राजकुमार पासवान,बिनोद ठाकुर,भीम नारायण यादवअशोक मंडल,प्रकाश कुमार,तनवीर आलम,दिलीप प्रामाणिक,बालदेव मंडल,अशरफ अली,प्रमोद कुमार यादव,अशोक यादव,रिंकू शेख सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

'क्या तकलीफ है'? कोमल रानी संग डेटिंग रूमर्स पर चीची ने तोड़ी चुप्पी, चर्चा करने वालों पर फूटा गुस्सा

अभिनेता गोविंदा लंबे वक्त बाद फिल्म 'रूपा' के जरिए कमबैक करने जा रहे हैं। इसमें उनके साथ अभिनेत्री कोमल रानी नजर आएंगी। इस फिल्म की चर्चा के साथ-साथ गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में हैं। कोमल रानी के साथ उनके कथित अफेयर की चर्चा फिल्मी गलियारों में चल रही हैं। इस बीच बीते दिन जब दोनों साथ में लाल बाग के राजा के दर्शन पहुंचे तो इन अफवाहों को और हवा मिल गई। इन पर अब गोविंदा ने प्रतिक्रिया दी है। बोले- 'करिश्मा कपूर और रवीना के साथ भी गया हूं मंदिर': गोविंदा ने कहा कि लाल बाग के राजा के पंडाल में कोमल के साथ जाना उनकी आगामी फिल्म से जुड़ा था। साथ ही कहा कि अफेयर की चचाएं उनके परिवार से दूर करने और उनकी इमेज खराब करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं। गोविंदा ने कहा, 'मैं अपनी फिल्म 'रूपा' के लिए प्रार्थना करने लाल बाग के राजा के दर्शन करने गया था। इससे पहले मैं करिश्मा कपूर के साथ भी मंदिरों में जा चुका हूं। वे मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ था। मेरी फिल्में बहुत बड़ी हिट रही थीं। मैं रवीना टंडन के साथ भी गया था। अब रानी स्वर्णकार के साथ गया हूं। मैंने प्रार्थना की, क्योंकि मैं लंबे समय बाद फिर से शुरू कर रहा हूं।

पूछा- 'लोगों को क्या परेशानी है'? : गोविंदा ने कोमल रानी स्वर्णकार संग डेटिंग की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, 'मैंने अभी-अभी फिल्म शुरू की है और अभी से ही इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम मशहूर हो रहे हैं तो लोगों को क्या परेशानी है'? इसके बाद गोविंदा ने दावा किया कि यह विवाद अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उनकी छवि खराब करने की सोची-समझी कोशिश का हिस्सा था। 'मैंने काम के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया': गोविंदा ने पर्सनल लाइफ को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर कहा, 'यह किसी की गलती नहीं है। यह बहुत सोच-समझकर बनाया गया प्लान था। ऐसा और भी होगा। यह मुझे मेरे परिवार से दूर करने और फिर समाज में मेरी इमेज खराब करने के प्लान का हिस्सा था। उन्होंने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। भगवान मेरे साथ थे। मैंने अपने काम के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस काम करता रहा। कई लोग मेरे अच्छे व्यवहार की तारीफ करते थे। वे कहते थे कि मैं सादगी और अच्छाई में बहुत डूबा हुआ हूं।

'द वन'- मूवी रिव्यू

वन देवी की लोककथा, छठी मइया की आस्था और रहस्य से भरी कहानी

, 7,लीड

हमारे देश में कहानियों की कोई कमी नहीं है, कमी है उन्हें बड़े पर्दे पर नए अंदाज में सुनाने की।

द वनः फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट बिहार की मिट्टी से निकली ऐसी ही एक लोककथा को लेकर आती है, जहां वन देवी, रहस्यमयी जंगल, छठी मइया की आस्था और इंसान की अपनी सोच आमने-सामने आती है।

फिल्म की शुरूआत जितनी दिलचस्पी जगाती है, उतना ही सवाल भी छोड़ती है कि जंगल के अंदर आखिर है क्या?

अच्छी बात यह है कि फिल्म काफी देर तक इस सवाल को जिंदा रखती है, बस बाद में जब जवाब मिलने शुरू होते हैं तो कुछ रहस्य उतने रहस्यमयी नहीं रह जाते।

फिल्म की कहानी कैसी है : कहानी ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की है, जो अपनी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के साथ बिहार के पुश्तैनी गांव आता है।

शहर में पले ऋषि के लिए गांव और उसकी मान्यताएं पुरानी सोच का हिस्सा हैं। दोनों का अपना पारिवारिक दर्द भी है और छठ के लिए घर लौटने का रिश्ता भी।

गांव के पास एक जंगल है, जिसके बीच वन देवी का मंदिर

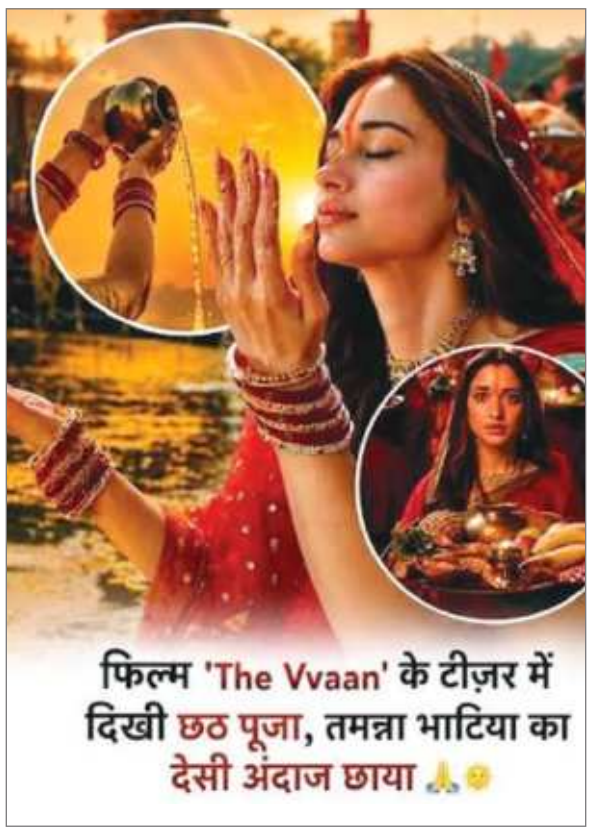

है। स्थानीय लोककथा के मुताबिक सूर्यास्त के बाद इस जंगल में जाना मना है।

फिल्म की प्रेरणा बिहार के बिहटा स्थित वन देवी मंदिर से जुड़ी इसी लोककथा से ली गई है, जहां जंगल और देवी को लेकर पीढ़ियों से कई मान्यताएं चली आ रही हैं।

फिल्म की कहानी यह एक तार्किक और शहरी युवक (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की कहानी है जो अपने पैतृक गांव लौटता है और एक जंगल के नियमों को तोड़ देता है।

फिल्म की कहानी यह एक तार्किक और शहरी युवक (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की कहानी है जो अपने पैतृक गांव लौटता है और एक जंगल के नियमों को तोड़ देता है।

ऋषि इन बातों को नहीं मानता। इसी बीच जंगल को लेकर विकास और प्रकृति के बीच खींचतान सामने आती है, लेकिन जब ऋषि जंगल में पहुंचता है और एक पुरानी मुहर टूटने के बाद अलौकिक ताकत जागती है, तब उसकी अपनी सोच भी सवालों के घेरे में आ जाती है।

पहला हिस्सा यहीं सबसे ज्यादा पकड़ बनाता है। गांव का माहौल, रिश्ते, हल्का हास्य और जंगल का रहस्य साथ-साथ चलते हैं। लेकिन दूसरे हिस्से में कहानी प्रकृति और जमीन के सवाल से निकलकर सीधे अच्छाई बनाम बुराई की बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ जाती है।

इससे शुरूआत में बना वह जमीन से जुड़ा संघर्ष थोड़ा पीछे छूटता है। कहानी में विचार कम नहीं हैं, बस कुछ विचारों को पूरी तरह खुलने का मौका नहीं मिलता।

फिल्म में एक्टिंग कैसी हैः सिद्धार्थ मल्होत्रा ऋषि के किरदार में एक्शन के साथ भावनात्मक बदलाव भी संभालते हैं। उनका अविश्वास धीरे-धीरे विश्वास में बदलता है, हालांकि इस बदलाव को थोड़ा और समय मिलता तो किरदार और गहराता।

तमन्ना भाटिया सहज लगती हैं और सिद्धार्थ के साथ उनकी पति-पत्नी वाली केमिस्ट्री फिल्म के फैंटेसी हिस्से को मानवीय आधार देती है। उनके किरदार में संभावनाएं हैं, लेकिन स्क्रीनप्ले उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करता।

सुनील ग्रोवर फिल्म का अच्छा सरप्राइज हैं। गंभीर किरदार में उनका अंदाज अलग लगता है और उनकी कहानी खुलने के साथ उत्सुकता बढ़ती है। मनीष पॉल पहले हिस्से में हंसी और हल्कापन लाते हैं। श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी अपने किरदारों में ठीक बैठते हैं। फिल्म का निर्देशन कैसा हैः निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने बिहार की एक कम सुनी गई लोककथा को सिर्फ डर की कहानी नहीं बनाया। इसमें परिवार है, प्रकृति है, आस्था है, विकास का सवाल है और फैंटेसी भी है।

दिक्कत बस यही है कि इतनी सारी चीजों को साथ लेकर चलने की कोशिश में स्क्रीनप्ले कभी-कभी खुद अपनी रफ्तार से आगे निकल जाता है। शुरूआत में जो रहस्य धीरे-धीरे बनता है, बाद में उसके कई जवाब जल्दी मिल जाते हैं। कुछ चीजें अगर थोड़ी देर और छिपी रहतीं तो जंगल का रोमांच और टिक सकता था।

सिनेमैटोग्राफी फिल्म की बड़ी ताकत है। जंगल की हरियाली, धुंध, अंधेरा और रोशनी मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि कई बार जंगल खुद कहानी का किरदार लगता है।

प्रोडक्शन डिजाइन में बिहार की मिट्टी और गांव की पहचान बनी रहती है। रहस्यमयी जीवों और पुराने घटनाक्रम को समझाने वाला एनीमेशन भी फिल्म का दिलचस्प प्रयोग है।

वीएफएक्स में पैमाना बड़ा रखा गया है। कुछ दृश्य शानदार लगते हैं, जबकि कुछ जगह कंप्यूटर से बने हिस्से उतने सहज नहीं बैठते। बड़े पर्दे पर फिल्म का स्केल जरूर दिखाई देता है।

फिल्म 'लव एंड वॉर' से आलिया का पहला लुक आउट,कैबरे आर्टिस्ट के अवतार में दिखीं एक्ट्रेस, फ्लांट किए रिप्ड एब्स

संजय लीला भंसाली फिल्म लव एंड वॉर का दूसरा पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म के पहले लुक में जहां रणबीर कपूर की झलक सामने आई थी। वहीं आज फिल्म से आलिया भट्ट का लुक सामने आया है। मेकर्स ने आलिया के दो पोस्टर रिलीज कर फैंस का उनके किरदार से परिचय कराया है। पोस्टर में वह अपनी सभी फिल्मों के लुक्स के बेहद अलग दिखाई दे रही हैं।

रेट्रो लुक में दिखीं आलिया भट्टः फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का लुक काफी ग्लैमरस दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर में उन्हें कुर्सी पर अदाओं के साथ बैठे हुए दिखाया गया है। वहीं उनके बैकग्राउंड में पुराने दौर का क्लब दिख रहा है, जहां एक स्टेज के आस पर कई लोग खड़े हुए हैं। पोस्टर को देखते हुए लग रहा है कि उनका किरदार किसी कैबरे डांसर का हो सकता है। इसके पोस्टर के साथ मेकर्स ने

कैप्शन में 'आग भी, दिलों की जान भी' लिखा है। इससे पता चल रहा है कि फिल्म में उनका किरदार लोगों के बीच काफी मशहूर है।

आलिया का दूसरा लुक भी कातिल3 फिल्म 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट का दूसरा लुक भी दिखाया गया है। इस पोस्टर में पूरी तरह कैबरे डांसर लुक में नजर आ रही हैं। पोस्टर में वह स्टेज पर अपने जलवे बिखेर रही हैं। एक्ट्रेस की पुरानी सभी फिल्मों से यह लुक काफी अलग है।

पहले पोस्टर में था रणबीर कपूर का लुक : फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में रणबीर विंटेज कार चलाते दिखाई दिए थे। वो एक हाथ से ड्राइव कर रहे थे। वहीं उनका दूसरा हाथ जख्मी था और उससे खून बह रहा था। बता दें कि भंसाली की यह कहानी पुराने दौर के सेट है। फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एडिटर और कंपोजर सब कुछ खुद भंसाली ही हैं। बताते चलें कि इस फिल्म के जरिए रणबीर और भंसाली लगभग 19 साल बाद साथ काम करेंगे। 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'सांवरिया' में दोनों ने आखिरी बार साथ काम किया था।

पहले भी रह चुकी हैं भंसाली की फिल्म का हिस्साः एक्ट्रेस आलिया भट्ट पहले भी संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में काम कर चुकी हें। फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला था। फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित थी। इस फिल्म की कहानी में मायानगरी की बदनाम गलियों की दास्तान दिखाई गई थी।

मुथूट फिनकॉर्प नया स्पांसर, दो घरेलू सीजन के मिले अधिकार, 35 इंटरनेशनल मैचों में पहुंचेगा लोगो

एजेंसी/ मुंबईः भारतीय क्रिकेट के अगले दो घरेलू सीजन के लिए मुथूट फिनकॉर्प नया टाइटल स्पांसर बन गया है। कंपनी को भारत में होने वाले इंटरनेशनल और घरेलू मैचों के टाइटल स्पांसरशिप राइट्स 31 मार्च, 2028 तक मिले हैं। इस दौरान करीब 35 घरेलू इंटरनेशनल मैच होंगे। इस स्पांसरशिप को ब्लू मुथूट नाम से पेश किया जाएगा। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, डील की बातचीत 4.85 करोड़ रुपए प्रति मैच के बेस प्राइस पर हुई है। हालांकि बीसीसीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही बेस प्राइस की स्थिति साफ होगी। इस दौरान भारत में 10 टेस्ट, 12 वनडे और 13 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। यह डील तुरंत प्रभावी होगी। इसका असर 27 सितंबर से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में दिखाई देगा।

खास बात यह है कि सीरीज का पहला मैच मुथूट के गृह राज्य केरल में खेला जाएगा। पहला वनडे 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में होगा। 1997 में स्थापित हुई मुथूट फिनकॉर्प, कोच्चि के मुथूट परिवार की कंपनी है। नए टाइटल स्पांसर की घोषणा में देरी हुई थी। इसकी एक वजह अधिकारों के लिए गंभीर बोलीदाताओं की कमी बताई गई। ऊंची बेस कीमत भी इसकी वजह रही।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तीन साल तक रहा स्पांसरः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सितंबर, 2023 से अगस्त, 2026 तक बीसीसीआई का टाइटल स्पांसर था। तीन साल की इस डील के तहत बैंक भारत में होने वाले पुरुष और महिला दोनों के इंटरनेशनल और घरेलू मैचों का टाइटल स्पांसर रहा। इसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बीसीसीआई को प्रति मैच 4.2 करोड़ रुपए देता था। अगस्त, 2026 में डील खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने नए टाइटल स्पांसर की तलाश शुरू की।

नहीं रहे वेलकम फेम मुश्ताक खान, कैंसर से निधन, शोक

फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का गुरुवार को निधन हो गया। वेलकम , आशिकी , मुझसे शादी करोगी और हम हैं राही प्यार के जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले मुश्ताक खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि मुश्ताक खान पिछले करीब 15 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे। वह कैंसर से जूझ रहे थे।

उन्हें करीब पांच साल पहले कैंसर का पता चला था, लेकिन हाल ही में बीमारी दोबारा लौट आई थी। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। मुश्ताक खान के बिजनेस पार्टनर शिवम ने उनके निधन की पुष्टि की है। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर है।

एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटी ने दस हजार मीटर रेस में जीता कांस्य पदक

महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में 32:41:54 का समय निकाल जीता ब्रॉन्ज मेडल

चंबाः जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीट और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की उड़नपरी सीमा कुमारी ने इतिहास रच दिया है। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस इवेंट में सीमा ने 32:41:54 सेकंड का समय निकालते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में यह उनका पहला मेडल है। इसके साथ ही सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर इवेंट में भारत का 16 साल लंबा मेडल का सूखा भी खत्म कर दिया है।सीमा का यह ऐतिहासिक मेडल सिर्फ ट्रैक पर उनकी तेज रफ्तार का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उस साहस, गरीबी और संघर्ष की जीत है, जिसकी शुरूआत हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से नंगे पैर हुई थी। उल्लेखनीय है कि सीमा ने 24 से 28 जून तक भुवनेश्वर के

कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनीयर प्रतियोगिता में दस हजार मीटर की दौड 34:28:75 में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस शानदार प्रदर्शन के चलते सीमा का चयन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ था। सीमा के कांस्य पदक जीतने की सूचना के बाद भारत सहित चंबा जिला में जश्न का माहौल है। गौर रहे कि सीमा चंबा जिला के रेटा गांव की रहने वाली है। इससे पहले भी सीमा कई स्वर्ण सहित अन्य पदक जीत चुकी है।

धर्मशाला के साई सेंटर में निखरा सीमा का हुनरः भारत की उड़नपरी और धर्मशाला के साई केंद्र की धाविका सीमा ने एशियाई गेम्स में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। सीमा की इस उपलब्धि से धर्मशाला स्थित साई केंद्र में भी खुशी का माहौल है। चंबा की रहने वाली सीमा के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के सफर की नींव धर्मशाला के साई केंद्र में ही पड़ी थी। यहां प्रशिक्षण के दौरान उनकी प्रतिभा को एथलेटिक्स कोच केएस पटियाल ने तराशा। कठिन प्रशिक्षण और लगातार मेहनत के दम पर सीमा ने राष्ट्रीय और युवा स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक अपने नाम किए और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कायम किए। सीमा के प्रशिक्षक केएस पटियाल ने खुशी जताते हुए कहा कि सीमा ने धर्मशाला में प्रशिक्षण के दौरान जिस मेहनत और अनुशासन का परिचय दिया था, उसका परिणाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई दे रहा है।

भारतीय कबड्डी टीमों का कमाल, एशियन गेम्स में पुरुषों के बाद महिलाएं भी सेमीफाइनल में

एजेंसी/ आइची नागोयाः मौजूदा चैंपियन भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने गुरुवार को ग्रुप ए के अपने मुकाबलों में क्रमशः चीनी ताइपे और जापान को हराकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष टीम ने जहां ग्रुप के अपने अंतिम मुकाबले में चीनी ताइपे को 37-21 से हराया, वहीं भारतीय महिला टीम ने मेजबान जापान को 50-25 से हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम की यह ग्रुप चरण में लगातार चौथी जीत थी। इससे पहले भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया, जापान और बांग्लादेश को हराया था।

इस तरह भारत ने ग्रुप चरण में अपने सभी मुकाबले जीतकर

कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया। भारत ने शुरूआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और हाफ टाइम तक 23-11 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा और इस दौरान 14-10 से आगे रही। भारत ने सफल रेड से 28 अंक, तीन बोनस अंक और ऑलआउट से छह अंक हासिल किए।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका-चीन आपस में भिड़ने से बचें, व्हाइट हाउस पहुंचने पर बोले जिनपिंग, ट्रंप ने कहा, दोनों देश अच्छे दोस्त

एजेंसी/ वाशिंगटन: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। अमेरिकीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोडकर खुद एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसमें एआई का मुद्दा सबसे अहम था। जिनपिंग ने एआई को लेकर कहा कि इसका नियंत्रण हमेशा इनसानों के हाथ में रहना चाहिए। जिनपिंग ने अमेरिका और चीन के बीच टकराव से बचने की अपील की। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन दोस्त हैं। उनके हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका के किसी भी बड़े टीवी चैनल ने इस मुलाकात का लाइव प्रसारण नहीं किया। दरअसल, व्हाइट हाउस ने सीएनएन, एमएस नॉउ और पॉलिटिको के पत्रकारों को कवरेज से रोक रखा है।

इसके विरोध में दूसरे चैनल भी इस मुलाकात को कवर नहीं कर रहे हैं। बता दें कि जिनपिंग 11 साल बाद व्हाइट पहुंचे हैं। जिनपिंग आखिरी बार 2015 में बराक ओबामा के समय व्हाइट हाउस गए थे। तब दोनों देशों के बीच व्यापार, जलवायु और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग की बात होती थी। अब दोनों देशों के बीच एआई चिप, दुर्लभ खनिज, सैन्य ताकत और ताइवान को लेकर बढ़े तनाव पर चर्चा हो रही।

ब्रिटेन के बॉर्डर पर बढ़ी चिंता, लगातार दो दिन बिना रोक-टोक तट तक पहुंचीं प्रवासियों से भरी नावें

लंदन : ब्रिटेन की समुद्री सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। लगातार दो दिनों तक छोटी नावों के जरिए सैकड़ों अवैध प्रवासियों के बिना किसी रोक-टोक केंट तट पर पहुंचने के बाद ब्रिटिश सरकार हरकत में आ गई है। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने इस गंभीर चूक पर सख्त रुख अपनाते हुए पूरे मामले की तत्काल उच्चस्तरीय समीक्षा के आदेश दिए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बॉर्डर फोर्स का नावों को तट तक पहुंचने से न रोक पाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

डोवर तट पर 21 हिरासत में, तस्करों ने बदला घुसपैठ का पैंतराः यह मामला तब गरमाया जब डोवर के सैम्फायर हो बीच पर अवैध प्रवासियों से भरी एक नाव सीधे किनारे आ पहुंची, जिसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को हिरासत में ले लिया। आमतौर पर इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रवासियों को बॉर्डर सिक्योरिटी या लाइफबोट्स द्वारा बीच समंदर में ही इंटरसेप्ट कर किनारे लाया जाता है। होम सेक्रेटरी ने बताया कि निगरानी सख्त होने के कारण मानव तस्करों ने अब अपने तौर-तरीके बदल लिए हैं। अब वे फ्रांस के पश्चिमी तटों से नावें रवाना कर रहे हैं, जिससे प्रवासियों को और अधिक लंबे व जानलेवा समुद्री रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है।

विपक्ष का तीखा हमलाः अराजक हुई सीमा सुरक्षा, फ्रांस से नहीं हो रही कोई रोक-टोक

इस घटना को लेकर ब्रिटेन की घरेलू सियासत भी गरमा गई है। मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिल्प ने सरकार की घेराबंदी करते हुए इसे पूरी तरह खुली छूट करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटेन की बॉर्डर सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और फ्रांस की तरफ से भी इन खतरनाक नावों को रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं दिख रहा है।

आंकड़ों में 45 फीसदी की गिरावट, फिर भी चूक पर अलर्ट मोड में सरकार3 सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक लगभग 17,784 प्रवासी छोटी नावों के सहारे इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 2026 में यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 45 फीसदी कम दर्ज किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि सितंबर 2025 में सिर्फ एक नाव बिना एस्कॉर्ट के तट तक पहुंच सकी थी। इसके बावजूद लगातार दो दिनों में हुई इस भारी चूक के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड को पूरी कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह नकेल कसी जा सके।

इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बन जाएं ज्ञानेश कुमार, राहुल बोले, देशद्रोह कर बच नहीं पाएंगे

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, एसआईआर और वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों पर 55 मिनट की प्रेस कान्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी की है। वह देशद्रोही हैं। मैंने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और उन्हें समझना चाहिए कि वह देश के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य काम नहीं हो रहा है, बल्कि संविधान पर हमला किया गया है और उसे कमजोर करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और वोट चोरी करवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आदि के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश में शामिल हैं। वोट चोरी देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है और देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की यह साजिश देशद्रोह है। वोट चोरी करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ वह चुप नहीं बैठेंगे।

उन्होंने कहा कि देश में सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इनकंबेंसी) कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के खिलाफ तो काम करती है, लेकिन भाजपा के खिलाफ गायब हो जाती है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध के बाद भारी लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन कुछ ही समय में उनके खिलाफ भी सत्ता विरोधी माहौल बन गया। यही स्थिति कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ भी होती है, लेकिन भाजपा के मामले में ऐसा नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि मैं पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में धांधली हुई। मेरे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यह 99 प्रतिशत नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत निश्चित है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले वोट चोरी हुई, फिर कानून चोरी हुई और अब संस्थाओं की चोरी हो रही है।

चुनाव आयोग पर सियासी तूफान, विपक्ष हमलावर, प्रियंका बोलीं, देशद्रोह के आरोप में सीईसी पर चले मुकदमा

नई दिल्ली: देश के अंदर चुनाव आयोग को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यदि किसी तरह अनुचित एवं अवैध काम हुआ है तो मुख्य चुनाव आयुक्त सहमति जो भी जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयुक्तों में मतभेद होने की रिपोर्ट पर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देने का किसी भी तरह का प्रयास देश के संविधान के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब बहुत ही स्पष्ट है। हमारे चुनाव की लोकतांत्रित प्रकिया के साथ यदि कोई भी खिलवाड़ करता है तो यह देशद्रोह है। इस पर हमारा रुख बिलकुल स्पष्ट और साफ है।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाना गंभीर अपराध होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में हेरफेर करना, मेरा मानना है कि 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाना,लोकतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ एक आपराधिक कृत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त को अनियमितताओं की जानकारी थी, साथी चुनाव आयुक्तों ने उन्हें इस बारे में सूचित किया था और इसके बावजूद उन्होंने इसे जारी रहने दिया, तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग के लिए आज देशभर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेसः कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर देशभर में आंदोलन करने की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव-संगठन केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले दिन से ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में हो रहे चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की कवायद को उजागर कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक दिन पहले जो खुलासे सामने आए हैं उन खुलासों के बाद लोकतंत्र के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त का कथित राष्ट्रविरोधी कृत्य स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर सडकों पर उतरेगी और उसने अपनी सभी प्रदेश इकाइयों को 25 सितंबर को अपने राज्य के निर्वाचन आयोग कार्यालयों तक बड़े पैमाने पर विरोध मार्च आयोजित करने को कहा है।

कानपुर में कारोबारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा

बहू नहीं बेटा निकला बाप का कातिल, नौकर ने खोला राज

कानपुर :कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, कारोबारी का बेटा सुब्रत मिनोचा ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने बहू शालू मिनोचा, नौकर विशाल गौतम और उसके साथी राजकिशोर को 24 घंटे के कस्टडी रिमांड पर लिया। कारोबारी के बेटे सुब्रत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। देर शाम तक पुलिस की तीन टीमों ने तीन राउंड में अलग-अलग पूछताछ की। हर राउंड की पूछताछ के साथ सुब्रत पर पुलिस का शिकंजा कसता चला गया।

हत्यारोपी नौकर विशाल पूछताछ में पहले शालू का नाम लेता रहा। बाद में उसने पुलिस के सामने बयान बदला और कहा कि उसने सुब्रत भइया के कहने पर विनीत मिनोचा की हत्या की थी। विशाल के मुताबिक, सुब्रत ने उससे कहा था कि अगर पकड़े जाओ तो शालू का नाम लेना।

तीन राउंड की पूछताछ के बाद विशाल के बयानों, डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, साजिश

रचे जाने के दौरान उसकी मौजूदगी और उसके साथ हुई चैट के आधार पर पुलिस ने सुब्रत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े रक्तरंजित कपड़े और फ्लैट की चाबी भी बरामद कर ली है।

पुलिस लाइन में हुई पूछताछ के दौरान पुलिस आयुक्त और डीसीपी पश्चिम ने पहले अलग-अलग और फिर सुब्रत, शालू व विशाल को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की। शुरूआत में विशाल लगातार शालू पर साजिश रचने का आरोप लगाता रहा। पुलिस ने जब सवालों की बौछार की तो उसने कहा कि हत्या सुब्रत के कहने पर की गई थी। विशाल ने बताया कि उसने शुरूआत में शालू का नाम इसलिए लिया क्योंकि वह बहुत डर गया था।

इसके बाद पुलिस ने सुब्रत से उसके खिलाफ मिले डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों तथा लोकेशन को लेकर सवाल किए। पुलिस को सुब्रत और विशाल के बीच हुई चैट भी मिली है। वहीं, शालू से पूछताछ में उसने हत्या की जानकारी से इनकार किया। उसने कहा कि विशाल ने उसका नाम क्यों लिया, उसे इसकी जानकारी नहीं है।

जब पुलिस ने शालू को सुब्रत पर लगे आरोपों के बारे में बताया तो वह रो पड़ी। उसने कहा कि सुब्रत उसे फंसा रहा है। शालू के मुताबिक, उसे हत्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम।

18 दिन बाद पति को सामने देखती रही शालू, आंखों में छलका दर्दः पुलिस कस्टडी रिमांड में 18 दिन बाद पति सुब्रत को सामने देखकर शालू उसे एकटक निहारती रही। पुलिस की पूछताछ के बीच दोनों का आमना-सामना कराया गया। शालू ने आंखों ही आंखों में सुब्रत से कई सवाल किए। जेल जाने के बाद पति एक बार भी मिलने नहीं आया और विशाल के बयान के आधार पर उसे हत्या की साजिशकर्ता मान लिया गया–जैसे सवाल उसके मन में कौंध रहे थे।

इस दौरान सुब्रत नजरें चुराता रहा। जब उसने पिता की हत्या का आरोप शालू पर मढ़ दिया तो वह फूट-फूटकर रो पड़ी। शालू ने आरोप लगाया कि सुब्रत खुद को बचाने के लिए उसे फंसा रहा है। करीब एक घंटे चले आमना-सामना के दौरान शालू तीन से चार बार रोई। उसने कहा कि सुब्रत पर से उसका विश्वास अब पूरी तरह टूट गया है।

बिहार में फिर शर्मसारः मंदार पर्वत पर लड़की से दरिंदगी की कोशिश, डंडे और चप्पल लेकर मनचलों ने घेरा, वीडियो वायरल

बांकाः बिहार में युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जमुई और समस्तीपुर की सनसनीखेज वारदातों के बाद अब बांका जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मंदार पर्वत से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। मंदार पर्वत परिसर में कुछ दबंग मनचलों द्वारा एक बेबस लड़की और उसके साथियों के साथ सरेआम अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

हाथ पकड़कर घसीटा, चप्पल-डंडे से पीटने की दी धमकी : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खौफनाक वीडियो में 3 से 4 दबंग युवक एक लड़की को चारों तरफ से घेरकर धमकाते नजर आ रहे हैं। इनमें से एक सिरफिरे लड़के के हाथ में डंडा और दूसरे के हाथ में चप्पल दिखाई दे रही है। दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपी लड़की का हाथ जबरन पकड़कर खींचते दिखे और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां देते रहे। पीड़िता खौफ के साए में कांपती नजर आई। जब उसके साथ मौजूद साथियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी जमकर पीटा और गाली-गलौज की।

हरकत में आया पुलिस महकमा, 7 अज्ञात बदमाशों पर एफआईआर दर्जः वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही बांका पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की नजाकत को भांपते हुए बौंसी थाना पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच तेज कर दी। बौंसी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर पंकज कुमार झा भारी पुलिस बल के साथ खुद मंदार पर्वत पहुंचे। स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ में तस्दीक हुई कि यह शर्मनाक वारदात मंदार पर्वत परिसर की ही है और आरोपी स्थानीय लड़के हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना अप्रैल महीने के आसपास की बताई जा रही है। थानाध्यक्ष के बयान पर 6 से 7 अज्ञात मनचलों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

जमुई और समस्तीपुर में हो चुकी है कड़ी कार्रवाई, अब बांका पर नजरें : बिहार में युवतियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर पुलिस का रुख बेहद कड़ा रहा है। इससे पहले जमुई के मड़वा पहाड़ी पर छात्रा से बदसलूकी करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर दबोचा था, जबकि समस्तीपुर के कपूरी ग्राम में भी छेड़खानी के 4 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। ऐसे में अब मंदार पर्वत की पवित्र धरती को कलंकित करने वाले इन गुंडों की गिरफ्तारी को लेकर बांका पुलिस की कार्यशैली पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं।

सावधान! बिना सिगरेट छुए भी जा रही जान, भारत में पैसिव स्मोकिंग ने ली 3.25 लाख जिंदगियां, लैंसेट की डरावनी रिपोर्ट

नई दिल्ली: अगर आपके घर या दफ्तर में कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो यह खबर आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक बेहद गंभीर खतरे की घंटी है। विश्वप्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ की हालिया रिपोर्ट में एक दिल दहला देने वाला तथ्य सामने आया है कि भारत में बिना सिगरेट पिए सिर्फ दूसरों के छोड़े गए धुएं यानी पैसिव स्मोकिंग (सेकंड-हैंड स्मोक) के संपर्क में आने से हर साल लाखों लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं। देश में साल 1990 के बाद से पैसिव स्मोकिंग के कारण होने वाली मौतों में लगभग 50 फीसदी का जानलेवा उछाल दर्ज किया गया है।

लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार, साल 1990 में भारत में सेकंड-हैंड स्मोक के कारण 2,17,700 मौतें दर्ज की गई थीं, जो साल 2023 में बढ़कर 3,25,600 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गईं। यानी केवल एक वर्ष के भीतर तीन लाख से अधिक निर्दोष भारतीयों ने सिगरेट को हाथ लगाए बिना सिर्फ उसके धुएं के कारण दम तोड़ दिया। चीन के बाद पूरी दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोग पैसिव स्मोकिंग का शिकार बन रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, देश की करीब 44.4 करोड़ आबादी सीधे तौर पर इस जानलेवा धुएं की

चपेट में सांस लेने को मजबूर है।

पुरुषों के साथ महिलाएं भी चुका रहीं भारी कीमत, करोड़ों स्वस्थ जीवन के साल बर्बादः इस जहरीले धुएं का असर लिंगभेद से परे दोनों वर्गों पर समान रूप से कहर बरपा रहा है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, 1990 से 2023 के बीच पैसिव स्मोकिंग से जान गंवाने वाली महिलाओं की संख्या 1,13,400 से बढ़कर 1,56,900 पर पहुंच गई है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 1,04,300 से बढ़कर 1,68,700 दर्ज किया गया है। इस अदृश्य खतरे के चलते अकेले साल 2023 में भारतीयों ने कुल 92.8 लाख स्वस्थ जीवन के वर्ष हमेशा के लिए गंवा दिए। आबादी के तेज विस्तार के कारण हालांकि धुएं के संपर्क की दर में आंशिक गिरावट आई है, लेकिन पीड़ितों की कुल तादाद में 18.4 प्रतिशत का शुद्ध इजाफा हुआ है। हार्ट अटैक, कैंसर और स्ट्रोक का बड़ा कारण, बच्चे और बुजुर्ग सबसे आसान शिकारः स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पैसिव स्मोकिंग को सामान्य धुआं मान लेना जानलेवा भूल साबित हो सकता है। फोर्टिस अस्पताल के रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. ध्रुव आनंद के अनुसार, यह धुआं सीधे फेफड़ों, दिल और रक्त नलिकाओं पर हमला बोलता है। इसके निरंतर संपर्क से फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज , दिल का दौरा, स्ट्रोक, टाइप-2 डायबिटीज और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। खासकर बंद कमरों में धूम्रपान किए जाने पर अविकसित फेफड़ों वाले छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग सबसे जल्दी गंभीर श्वसन संक्रमण के शिकार बनते हैं। वैश्विक स्तर पर 16 लाख मौतें, घरों और गाड़ियों को स्मोक-फ्री जोन बनाने की सलाहः दुनियाभर में भी यह स्थिति विकराल रूप धारण कर चुकी है। साल 2023 में विश्व स्तर पर 2.71 अरब लोग सेकंड-हैंड स्मोक की जद में थे, जिससे 16.6 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हुई। चिंताजनक बात यह है कि दुनिया की आधी पीड़ित आबादी सिर्फ भारत, चीन और इंडोनेशिया में मौजूद है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ हिदायत दी है कि घरों, गाड़ियों और बंद सार्वजनिक स्थानों को पूरी तरह 100 फीसदी स्मोक-फ्री बनाया जाना चाहिए। धूम्रपान करने वालों को चाहिए कि वे अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए या तो इस लत को पूरी तरह त्याग दें अथवा केवल खुली जगहों पर ही सीमित रहें।

न्यूज IN ब्रीफ

2 अक्टूबर को व्यापारी मनाएंगे नो यूपीआई दिवस, काले कपड़े से ढकेंगे क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स

पटना : यूपीआई पर व्यापारियों से प्रस्तावित अतिरिक्त व्यापारी छूट दर (एमडीआर) के विरोध में 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन देशभर में ह्यनो यूपीआई दिवसह्ल मनाने का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में अखिल भारतीय ज्वेलर्स एवं स्वर्णकार महासंघ (एआईजीएफ) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि बिहार के आभूषण कारोबारी और अन्य व्यापारी भी इस अभियान में शामिल होकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों में लगे यूपीआई के क्यूआर कोड, स्कैनर और भुगतान की सूचना देने वाले ध्वनि यंत्र को काले कपड़े से ढकेंगे। इसके माध्यम से प्रस्तावित व्यापारी छूट दर के खिलाफ शांतिपूर्ण और सांकेतिक विरोध जताया जाएगा।

व्यापारियों का कहना है कि वे डिजिटल भुगतान व्यवस्था या यूपीआई के विरोध में नहीं हैं, बल्कि व्यापारियों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव को लेकर उनकी आपत्ति है। उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान आज व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क लगने से विशेष रूप से कम लाभांश पर कारोबार करने वाले छोटे और मध्यम व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पात्र 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई व्यापारी लेनदेन पर 15 अक्टूबर से 0.4 प्रतिशत व्यापारी छूट दर लगाने का प्रस्ताव है। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तक बताई गई है।

अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि व्यापारी डिजिटल भारत अभियान और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के सहयोगी हैं। उनका विरोध यूपीआई से नहीं, बल्कि व्यापारियों पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क के बोझ से है। ह्यनो यूपीआई दिवसह्ल के माध्यम से व्यापारी शांतिपूर्ण एवं सांकेतिक विरोध दर्ज कराते हुए सरकार से व्यापारी छूट दर के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग करेंगे।

उन्होंने बिहार के सभी आभूषण कारोबारियों और व्यापारियों से 2 अक्टूबर को अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर यूपीआई के क्यूआर कोड, स्कैनर और भुगतान सूचना देने वाले ध्वनि यंत्र पर काला कपड़ा लगाकर इस सांकेतिक विरोध में शामिल होने की अपील की है।

मानसिक तनाव में 16 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान

मेदिनीनगर : नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के खैरा दोहर गांव निवासी प्रमोद भुइयां की 16 वर्षीय पुत्री सुमन कुमारी ने मानसिक तनाव में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना गुरुवार शाम करीब चार बजे की है। गंभीर हालत में परिजन उसे छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान रात करीब आठ बजे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह अस्पताल पुलिस चौकी की पुलिस ने परिजनों से जानकारी लेकर शव का इंक्वेस्ट कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

करमा पूजा विसर्जन के दौरान कोयल नदी में डूबे हेमंत का शव बरामद

मेदिनीनगर : चैनपुर थाना क्षेत्र के बोकेया-पतरिया खुर्द गांव में करमा पूजा विसर्जन के दौरान कोयल नदी में डूबे आठ वर्षीय हेमंत कुमार सिंह का शव शुक्रवार को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। बुधवार को विसर्जन के दौरान तेज बहाव और गहरे पानी की चपेट में आने से पांच लोग नदी में डूब गए थे। इनमें हेमंत सिंह (8), नीतिश कुमार सिंह (18), अमित कुमार ठाकुर (22), राजा सिंह (12) और विशाल पासवान (16) शामिल थे। हेमंत का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

फॉर्म-6 संग्रहण कार्य की उपायुक्त ने की समीक्षा

मेदिनीनगर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण -2026 के तहत जिले में योग्य नागरिकों से फॉर्म-6 संग्रहण कार्य की जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज समाहरणालय सभागार में समीक्षा की। बैठक में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म-6 संग्रहण की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 1,19,943 योग्य मतदाताओं से फॉर्म-6 संग्रहण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरुद्ध अब तक 51,781 योग्य मतदाताओं से फॉर्म-6 का संग्रहण किया जा चुका है, जबकि 68,162 योग्य मतदाताओं से फॉर्म-6 का संग्रहण किया जाना शेष है।

उपायुक्त श्री शेखावत ने फॉर्म-6 संग्रहण की प्रगति पर चिंता जताते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रक्फ़के तहत कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाई जाये।

बैठक में कुछ विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एफ्ड) सभागार में उपस्थित रहे, जबकि कुछ एफ्ड के साथ-साथ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (अएफ्ड) वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में रक्फ़के तहत फॉर्म-6 संग्रहण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सीएसआर के नाम पर खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं, स्थानीय युवाओं को रोजगार दें कंपनियां : अमित गुप्ता

चंदवा : जिले में तेजी से विस्तार कर रही कॉरपोरेट कंपनियों की कार्यशैली और सामाजिक दायित्वों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कॉरपोरेट मामलों के विधायक प्रतिनिधि सह वरिष्ठ भाजपा नेता अमित कुमार गुप्ता ने कंपनियों को सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के नाम पर महज औपचारिकता निभाने के बजाय धरातल पर काम करने की नसीहत दी है। अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कंपनियां अपना कारोबार स्थापित कर रही हैं, वहां के स्थानीय लोगों ने विकास की उम्मीद में अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। ऐसे में कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं और क्षेत्र के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में कंपनियों को सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। केवल कागजों पर योजनाएं दिखाने या औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करने से सामाजिक दायित्व पूरा नहीं होता।

पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई

गुम हुए 97 मोबाइल बरामद, एसपी ने वास्तविक धारकों को सौंपे

मेट्रोरेज संवाददाता

मेदिनीनगर : पलामू पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 97 मोबाइल फोन बरामद कर शुक्रवार को एसपी कार्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके सत्यापित वास्तविक धारकों को सौंप दिया गया। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गुम मोबाइलों की बरामदगी के लिए सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल समेत अन्य तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की तकनीकी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए अलग-अलग स्थानों पर उपयोग किए जा रहे गुम मोबाइलों का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। बरामद मोबाइलों में अधिकांश पिछले दो माह के दौरान गुम हुए थे, जबकि कुछ मोबाइल इससे पहले गुम हुए थे।

एसपी ने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइलों का आवश्यक सत्यापन कराया गया। इसके बाद पहचान और दस्तावेजों के आधार पर उनके वास्तविक

धारकों की पुष्टि कर मोबाइल विधिवत उन्हें सौंपे गए। मोबाइल वापस मिलने के बाद धारकों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। एसपी कपिल चौधरी ने लोगों से अपील की कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने की स्थिति में बिना देर किए संबंधित थाना को सूचना दें और सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। इससे मोबाइल को तकनीकी माध्यम से ट्रैक करने और बरामद करने में पुलिस को मदद मिलती है।कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थाना प्रभारियों समेत पुलिस पदाधिकारी और मोबाइल प्राप्त करने वाले लोग मौजूद थे।

कृषि टास्क फोर्स की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, तेजी से कार्य करने का निर्देश

संवाददाता

छपरा : जिला समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी सारण वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में उर्वरक की उपलब्धता व वितरण, किसान पहचान पत्र, ई-केवाईसी, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्रीकरण, उद्यान एवं सिंचाई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला पदाधिकारी ने उर्वरक दुकानों में स्टॉक और वितरण की नियमित निगरानी तथा किसानों को वास्तविक रूप से उर्वरक मिलने का सत्यापन करने का निर्देश दिया। किसान पहचान पत्र निर्माण और ई-केवाईसी की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए दोनों कार्यों को अभियान चलाकर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने को कहा।

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत 30 सितंबर तक अधिक से अधिक किसानों से आवेदन लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही मृदा नमूनों की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने में तेजी लाने को कहा गया।

बैठक में उद्यान विभाग की केला, नारियल और मशरूम उत्पादन योजनाओं की भी समीक्षा हुई। सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में कम से कम एक मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित कराने की पहल करने का निर्देश दिया गया।

सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा के दौरान नहरों की साफ-सफाई, मरम्मत और खेतों तक पानी पहुंचने में आ रही बाधाओं का स्थल सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रखते हुए वास्तविक रूप से किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

मुनी बाबा धर्मशाला में 11 दिनों से विराजमान भगवान गणेश आज होंगे विसर्जित

संवाददाता

चक्रधरपुर के ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मुनी बाबा धर्मशाला में वर्ष 1946 से चली आ रही गणेश पूजा का आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर समापन होगा।

पिछले 11 दिनों से मुनी बाबा धर्मशाला में भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। प्रतिदिन विशेष आरती के साथ श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद और भोग का वितरण भी किया गया।

11 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। श्रद्धालुओं में विसर्जन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही 11 दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का समापन हो जाएगा।

27 सितंबर को डालटनगंज में होगा खेलो इंडिया वूमेन्स लीग

मेदिनीनगर : पलामू की बालिका खिलाड़ियों को वुशु खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 27 सितंबर, रविवार को खेलो इंडिया वूमेन्स लीग का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन रेड़मा, पांकी रोड, डालटनगंज स्थित द कराटे अकादमी में होगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 9 बजे किया जाएगा। पलामू वुशु एसोसिएशन की आम बैठक में बालिका वर्ग के खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। झारखंड वुशु एसोसिएशन के निर्देश पर 27 सितंबर को खेलो इंडिया वूमेन्स लीग आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग की महिला एवं बालिका खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगी। प्रतियोगिता में वुशु की दोनों प्रमुख विधाओं सांडा एवं ताउलू में मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

सिकनी कोलियरी चालू कराने की मांग तेज, 28 को निगम कार्यालय के समक्ष धरना

चंदवा : लंबे समय से बंद पड़ी सिकनी कोलियरी को पुनः चालू कराने की मांग को लेकर झारखंड कोलियरी मजदूर संघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संघ के बैनर तले आगामी 28 सितंबर को सिकनी कोलियरी स्थित निगम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय रोषपूर्ण धरना-प्रदर्शन एवं रैली का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव ने बताया कि सिकनी कोलियरी के लंबे समय से बंद रहने के कारण हजारों मजदूर, ट्रक मालिक, चालक, उपचालक समेत उनसे जुड़े परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कोलियरी के संचालन पर निर्भर लोगों के सामने रोजगार और आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

उन्होंने कहा कि कोलियरी को पुनः चालू कराने को लेकर कई बार निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया तथा आवश्यक पहल के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रबंधन की कथित उदासीनता के विरोध में संघ ने आंदोलन का निर्णय लिया है।

पुनः संचालन से हजारों परिवारों को मिलेगा रोजगार

झारखंड कोलियरी मजदूर संघ का कहना है कि सिकनी कोलियरी का पुनः संचालन क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ हजारों परिवारों की आजीविका बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। कोलियरी चालू होने से मजदूरों के अलावा परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

संघ ने मजदूरों, ट्रक मालिकों, चालकों एवं क्षेत्र के प्रभावित लोगों से 28 सितंबर को आयोजित धरना-प्रदर्शन एवं रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

अब देखना होगा कि आंदोलन के बाद निगम प्रबंधन सिकनी कोलियरी के पुनः संचालन को लेकर क्या कदम उठाता है।

तीन साल से एक ही जगह जमे 13 लिपिकों का तबादला

लातेहार : स्वास्थ्य विभाग ने एक ही संस्थान अथवा कार्यालय में तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से पदस्थापित 13 लिपिकों का स्थानांतरण कर दिया है। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार की ओर से जारी आदेश के बाद विभाग में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मियों की पदस्थापना अवधि को लेकर भी चर्चा तेज हो गयी है।

विभागीय आदेश के अनुसार, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं एवं उपायुक्त लातेहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में यह स्थानांतरण किया गया है। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत लिपिकों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थल से हटाकर दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है।

जारी स्थानांतरण आदेश के तहत सिविल सर्जन कार्यालय लातेहार में कार्यरत लिपिकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिका समेत अन्य संस्थानों में भेजा गया है। इसके अलावा सदर अस्पताल, बालूमाथ, महुआडांड़, चंदवा, मनिका, बरवाडीह और गारू सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थ लिपिकों का भी स्थानांतरण किया गया है।

सभी संबंधित कर्मियों को तीन दिनों के अंदर नवपदस्थापित संस्थान में योगदान देने के लिए विरमित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि तक विरमित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी 27 सितंबर 2026 के अपराह्न से स्वतः विरमित समझे जाएंगे।अन्य लंबे समय से पदस्थ कर्मियों की भी हो समीक्षा

13 लिपिकों के स्थानांतरण के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यालयों में लंबे समय से पदस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यावधि को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि सिविल सर्जन कार्यालय समेत स्वास्थ्य विभाग के कुछ कार्यालयों में ऐसे कर्मी अब भी कार्यरत हैं, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जब विभागीय निर्देश के तहत तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से एक ही संस्थान में कार्यरत लिपिकों का स्थानांतरण किया जा रहा है।

कृषि, पशुपालन व मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा, पात्र लाभुकों तक लाभ पहुंचाने का निर्देश

किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर उपायुक्त ने दिया जोर

लातेहार : उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि, पशुपालन, गव्य विकास एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि, लाभुक चयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों एवं लाभुकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे बीज, खाद, कृषि उपकरण, वर्षापात की स्थिति तथा बिरसा फसल विस्तार योजना वर्ष 2026-27 की प्रगति की जानकारी ली। इसके अलावा कृषक प्रशिक्षण, फसल उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करने तथा कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप

उपलब्धि हासिल करने और अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने पर जोर दिया।वहीं, मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं, लाभुक चयन एवं निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों की जानकारी ली गयी। उपायुक्त ने मत्स्य पालकों को योजनाओं से जोड़ने और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश

उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में संचालित योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने योजनाओं की नियमित निगरानी, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन करने पर जोर दिया।

बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ सुषमा प्रधिया, जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वर्णलता मधु लकड़ा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी हरि कृष्ण समेत संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।